कमल संदेश

ikf{kd if=dk

संपादक

प्रभात झा, सांसद

कार्यकारी संपादक

डॉ. शिव शक्ति बक्सी

सहायक संपादक

संजीव कुमार सिन्हा

संपादक मंडल सदस्य

सत्यपाल

कला संपादक

विकास सैनी

सदस्यता शुल्क

वार्षिक : 100/-
त्रि वार्षिक : 250/-

संपर्क

InL;rk : +91(11) 23005798
Qku (dk-) : +91(11) 23381428
QDl : +91(11) 23387887

पता : डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003

ई–मेल
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डॉ. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। सम्पादक – प्रभात झा

विषय–सूची

संगठनात्मक गतिविधियां

लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती........ 7
लद्दाख में भाजपा की भारी विजय........ 9

सरकार की उपलब्धियां

भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार........ 10
प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जमा हुए 25,000 करोड़ रुपये........ 11
प्रधानमंत्री ने डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी........ 12

श्रद्धांजलि

नई चुनौतियों की तलाश में रहते थे डॉ. कलाम........ 13

वैचारिकी

जीवन का ध्येय
पं. दीनदयाल उपाध्याय........ 14

बिहार विधानसभा चुनाव पर विशेष

मेसकौर, हसपुर और समस्तीपुर रैली........ 16
बक्सर/पालीगंज/आरा/सीवान........ 17
जहानाबाद और भभुआ रैली........ 18

लेख

एनजेएसी पर अदालत का निर्णय – एक वैकल्पिक दृष्टिकोण
–अरुण जेटली........ 21
भाजपायुक्त भारत की ओर बढ़ती भाजपा
– प्रभात झा........ 23
ईमानदारी और प्रतिबद्धता का दूसरा नाम केदारनाथ
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा........ 25

रिपोर्ट

महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण
–राम नयन सिंह........ 29

कमल संदेश के सभी सुधी पाठकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!

सोशल मीडिया से...

फेसबुक

श्री नरेंद्र मोदी

बिहार में चुनावी जनसभाओं में सभी जगह उमड़े अपार जन सैलाब से हवा का रुख साफ है। एनडीए भव्य विजय की ओर अग्रसर है। बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं को देखकर अच्छा लगा। आज का युवा अवसर चाहता है, विकास चाहता है। विकास सभी समस्याओं का समाधान है। मेरी योजना है- बिहार के हर गांव-कस्बे को बिजली, पानी और सड़क। युवाओं को पढ़ाई, कमाई और बुजुर्गों को दवाई।

.....

श्री अमित शाह

बिहार में नीतीश-लालू का गठबंधन होने से सबसे ज्यादा खुशी शहाबुद्दीन जैसे अपराधी लोगों को हो रही है और राज्य में अपराध का ग्राफ फिर से तेजी से बढ़ने लगा है। भारतवर्ष में श्रवण कुमार जैसे पितृभक्त हुए जिन्होंने अपने बूढ़े मां-बाप को अपने कंधे पर बिठाकर तीर्थाटन करवाया जबकि श्रीमान लालू जी अपने बेटों को कंधे पर बिठाकर राज्य की सैर करवाने चले हैं।

.....

श्री राजनाथ सिंह

डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जी का आर्थिक चिंतन हमें इस देश में गरीबी को खत्म करने का रास्ता दिखाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस द्वारा चिन्हित करके डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर जी के महान कार्य का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद।

.....

श्री सुशील कुमार मोदी

नीतीश कुमार सन्निपात रोगी की तरह परस्पर विरोधी बातें कर रहे हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा से भी परेशान होते हैं और यात्रा के दो-चार दिन टलने से भी। प्रधानमंत्री की सभाओं में भीड़ का उत्साह बिहार में सत्ता परिवर्तन की आंधी है। लालू-नीतीश उखड़ने से बचने के लिए जात-पात, भीतरी-बाहरी और तंत्र-मंत्र की रेत में शुतुर्मुर्ग की तरह सिर छिपा रहे हैं।

twitter

श्री नरेंद्र मोदी *@narendramodi*

वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं। महर्षि वाल्मीकि के विचारों ने हमेशा समाज को प्रेरित किया है।

.....

श्री अमित शाह *@AmitShahOffice*

हमारा मुख्य एजेंडा विकास है पर लालू प्रसाद विकास की बजाय अगड़ों-पिछड़ों के नाम पर समाज को बाँटने की कोशिश कर रहे हैं।

.....

श्री अरुण जेटली *@arunjaitley*

एलएएचडीसी चुनावों में ऐतिहासिक जीत पर लद्दाख की जनता और भाजपा को बधाई। भाजपा ने लद्दाख में एक नया अध्याय लिखा है।

.....

श्री नितिन गडकरी *@nitin_gadkari*

दिल्ली-जयपुर राजमार्ग में पिछले 12 महीनों में हुई प्रगति ने हमें विश्वास दिया है कि राजमार्ग क्षेत्र धीरे-धीरे, लेकिन लगातार पटरी पर आ रहा है।

.....

श्री जेपी नड्डा *@JPNadda*

मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को 'मन की बात' कार्यक्रम में अंगदान का मुद्दा उठाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

.....

श्री सुशील मोदी @SushilModi

गठबंधन को तोड़ना, लालू-सोनिया से हाथ मिलाना, मांझी को हटाना, ये तीन ऐसी गलतियाँ हैं जिसके लिए बिहार कभी नीतीश को माफ नहीं करेगा।

पाथेय

गोरक्षा

मैं गाय की पूजा करता हूं। यदि समस्त संसार इसकी पूजा का विरोध करे तो भी मैं गाय को पूजूंगा। गाय जन्म देने वाली मां से भी बड़ी है।

- महात्मा गाँधी

सम्पादकीय

बिहार में जंगलराज रोकने के लिए भारी मतदान

जैसे-जैसे बिहार में विभिन्न चरणों में मतदान हो रहा है लोग बड़ी संख्या में वोट डालने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। यह बहुत ही स्वागतयोग्य बात है कि लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं तथा अत्यधिक उत्साह से नई सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस बार मतदान का प्रतिशत पिछले बार से अधिक ही नहीं, महिलाओं की बड़ी भागीदारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह बहुत ही उत्साहजनक स्थिति है जिससे लोकतंत्र को बड़ी मजबूती मिली है। बिहार की धरती प्राचीनकाल से ही लोकतंत्र की जननी के रूप में जानी जाती है और हमेशा लोकतांत्रिक समाज एवं राजनीति की पक्षधर रही है। बिहार के लोग अपने लोकतांत्रिक विरासत के अनुरूप समाज के और अधिक लोकतंत्रीकरण के लिए मुखर है तथा समाज को बांटने वालों को कड़ा जवाब दे रहे हैं।

एक ओर जहां उच्च मतदान प्रतिशत का पूरे देश में स्वागत हो रहा है वहीं राजनैतिक पंडित इस प्रक्रिया को समझने को प्रयासरत हैं। लोकसभा चुनावों से ही मतदान प्रतिशत बढ़ा है और लगभग पूरे देश में यह प्रक्रिया तेज हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बढ़ा है और भविष्य के प्रति आशा जगी है। भविष्य के प्रति आशा तब जगती है जब विश्वसनीय एवं निर्णायक नेतृत्व हो तथा बेहतर विकल्प उपलब्ध हो। यह इस बात की ओर भी इशारा करता है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। देश लगातार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पर अपना विश्वास व्यक्त कर रहा है। नरेन्द्र मोदी लोगों की आकांक्षा के रूप में उभरे हैं तथा अपने सुशासन एवं विकास के रिकॉर्ड से लोगों में विश्वास पैदा करने में सफल रहे हैं। इन्हीं सब भावनाओं के साथ देश ने लोकसभा चुनावों में भाजपा को स्पष्ट बहुमत दिया। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखण्ड और जम्मू-कश्मीर के चुनावों में भी जनता ने भाजपा एवं नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अपना विश्वास दुहराया है। उनके अब तक के कार्यकाल ने लोगों के विश्वास को और मजबूत किया है जो पूरे विश्व में बसे भारतीयों के चेहरे पर स्पष्ट देखी जा सकती है। लोग विकास चाहते हैं, तीव्र विकास चाहते हैं, वे बेहतर अवसर तथा बेहतर जिंदगी चाहते हैं, इसलिए वे बड़ी संख्या में सुशासन एवं विकास के पक्ष में मतदान कर रहे हैं।

बिहार में जदयू-राजद-कांग्रेस ने जाति-संप्रदाय के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश की। वे समाज को बांट कर सत्ता हथियाना चाहते थे। वे बिहार के लिए कोई एजेण्डा प्रस्तुत नहीं कर पाये और उनके राज में बिहार के पिछड़ापन के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं है। लोगों को जंगलराज के वे दिन अब भी याद है जब कुछ भी सुरक्षित नहीं था- न जीवन, न सम्मान, न सम्पत्ति। आम आदमी भय और आतंक के साये में जी रहा था। कौन भूल सकता है कि जंगलराज में जो भी थोड़े-बहुत कल-कारखाने थे वे बंद हो गये थे तथा राज्य का युवा शिक्षा और रोजगार के लिए पलायन को मजबूर हो गया था। कानून-व्यवस्था पूरी तरह पंगु हो गई थी तथा केवल अपहरण एवं वसूली उद्योग फल-फूल रहा था। लोगों को यह सब अच्छी तरह से याद है और उन्हें अपने वोट की कीमत भी पता है। वे उन काले दिनों को फिर नहीं देखना चाहते इसलिए इसे हर हाल में रोकना चाहते हैं। लोग जंगलराज को रोकने तथा विकास एवं सुशासन का मार्ग प्रशस्त करने हेतु भारी संख्या में मतदान कर रहे हैं।

पिछले दो विधानसभा चुनावों से बिहार जंगलराज के विरूद्ध मतदान कर रहा है। वह एनडीए (तब भाजपा एवं जदयू) ही था जिसने लालू यादव को सत्ता से उतार कर जंगलराज का खात्मा किया था। परन्तु दुर्भाग्य है कि नीतीश अपनी अवसरवादी राजनीति के कारण फिर से जंगलराज की वापसी करना चाहते हैं। लालू यादव के साथ गठबंधन कर जंगलराज को पिछले दरवाजे से नीतीश कुमार लाना चाहते हैं। बिहार की जनता इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकती और इस चुनाव में नीतीश कुमार को सबक सिखाने को बेचैन है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा बिहार को सुशासन एवं विकास के मार्ग पर ले जाने को प्रतिबद्ध है। भाजपा को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। बिहार प्रगति के पथ पर चलने को आतुर है। बिहार अब पूरे देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है।

भाजपा ने बिहार के प्राचीन गौरव को पुन: प्राप्त करने की आशा जगायी है। ■

नेताजी से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक होंगी : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने नेताजी के परिजनों से कहा कि मैं आपके सुझावों को आगे ले जाऊंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के 35 सदस्यों ने 14 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से 7 रेसकोर्स रोड स्थित अपने निवास पर भेंट की।

एक घंटे चली बैठक के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों ने नेताजी से जुड़ी उन फाइलों को सार्वजनिक करने का आग्रह किया जो भारत सरकार के पास उपलब्ध हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत सरकार को नेताजी से जुड़ी उन फाइलों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया भी शुरू करनी चाहिए, जो विदेशी सरकारों के पास उपलब्ध हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नेताजी के परिवार के सदस्यों के सुझाव उनकी अपनी सोच और केंद्र सरकार के विचार से पूरी तरह मिलते-जुलते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इतिहास का गला घोंटने की कोई वजह नहीं दिखती। उन्होंने घोषणा की कि फाइलों को सार्वजनिक करने की प्रक्रिया नेताजी के जन्मदिन यानी 23 जनवरी, 2016 से शुरू की जाएगी।

प्रधानमंत्री ने नेताजी से जुड़ी उन फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए विदेशी सरकारों से अनुरोध करने पर भी सहमति जताई जो उनके पास उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि वह न केवल इस बारे में विदेशी सरकारों को पत्र लिखेंगे, बल्कि विदेशी नेताओं के साथ होने वाली बैठकों में भी यह मसला उठाएंगे। इसकी शुरुआत दिसम्बर में रूस से होगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जो देश इतिहास को भूल जाते हैं, वे इतिहास बनाने की शक्ति भी खो देते हैं। उन्होंने नेताजी के परिजनों से उन क्षणों को भी साझा किया जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान नेताजी को स्मरण किया करते थे।

प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों से कहा कि मुझे अपने परिवार का ही एक हिस्सा मानिए।

केन्द्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं श्रीमती सुषमा स्वराज और केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो भी इस मौके पर उपस्थित थे। ■

संपूर्ण क्रांति का मंत्र, संपूर्ण विकास के मंत्र में परिवर्तित हो : मोदी

लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ये भी विधि का योग है कि 11 अक्टूबर जयप्रकाश जी के अनन्य साथी, नाना जी देशमुख की भी जयंती है। आज प्रातः मुझे आदरणीय जॉर्ज साहब के यहां जा करके और आदरणीय अटल जी के यहां जा करके,

उनके आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। मैं इन सबको इसलिए स्मरण करता हूं कि जयप्रकाश जी के साथ संपूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ, अपने आप को खपा देने वाले ये महापुरूष रहे हैं। आपातकाल में जेपी पर प्रहार हुआ और अगर नाना जी देशमुख न होते, और वो वार नाना जी अपने शरीर पर न झेलते तो शायद जयप्रकाश जी नहीं बच पाते। श्री मोदी ने कहा अगर उस आपाताकालीन दिनों को याद करूं तो मैं बहुत ही एक छोटा सा कार्यकर्ता था। इन सभी वरिष्ठों के अंगुली पकड़कर चलने का सौभाग्य मिला। आपातकाल ने नुकसान बहुत किया। पूरे विश्व में हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक परंपरा को एक गहरा धक्का लगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में जो लोग दिखते हैं, उसमें से अधिकतम वो लोग हैं, जिनको उस आपात काल के संघर्ष की कोख में से पैदा होने का अवसर मिला था। विचार को समाप्त करने के लिए इमरजेंसी आई थी। व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए आई थी। लेकिन उस विचार में ताकत इतनी थी कि इतनी बड़ी जंजीरों के बीच भी, इतने जुल्म के बीच भी, एक पूरी नई राजनीतिक पीढ़ी पैदा हुई देश में। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो राजनीतिक पीढ़ी लोकतांत्रिक मूल्यों के रखवाले के रूप में पैदा हुई। श्री मोदी ने कहा कि मैं मानता हूं कि इस देश की मीडिया ने और चीजों के विषयों में उनकी राजी-नाराजगी हो सकती है, और चीजों में उनकी पसंद नापसंद हो सकती है। लेकिन उन्होंने कभी भी देश को आपातकाल के दिन भूलने नहीं देना चाहिए। हर बार स्मरण करना चाहिए क्योंकि आपातकाल ने सबसे बड़ा हमला बोला था, तो मीडिया की स्वतंत्रता पर बोला था और लोकतंत्र के जो मुख्य स्तंभ हैं उन सारे के सारे पिलरों पर वार किये थे। उसको खत्म करने का भरपूर प्रयास किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जयप्रकाश जी ने तीन दिन लगातार गुजरात में रह करके भ्रमण किया, तो मुझे भी उस समय व्यवस्था के तहत उन कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला उनके पास रहने का

आडवाणी, बादल सहित कई नेता सम्मानित

समारोह में जिन लोगों को सम्मानित किया गया उनमें पूर्व उपप्रधानमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी, शिरोमणि अकाली दल के स. प्रकाश सिंह बादल, चार राज्यपाल श्री कल्याण सिंह, श्री ओ पी कोहली, श्री बलराम दास टंडन और श्री बजूभाई वाला, लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर श्री करिया मुंडा के अलावा भाजपा नेता श्री वी के मल्होत्रा, श्रीमती जयंती बेन मेहता और श्री सुब्रमण्यम स्वामी शामिल हैं। श्री मोदी ने राकांपा नेता श्री डी पी त्रिपाठी, पत्रकार श्री वीरेन्द्र कपूर, श्री के विक्रम राव, प्रो. रामजी सिंह, श्री कामेश्वर पासवान और श्री आरिफ बेग को भी सम्मानित किया।

अवसर मिला और मैंने देखा कि भारत की दुर्दशा के प्रति जो आग थी उनके अन्दर, बोलने में तो वो उस प्रकार से नहीं थे, बड़ी मृदु भाषा बोलते थे, सरल और आवाज भी बड़ी धीमी रहती थी। लेकिन अन्दर से जो उबलते हुए ज्वाला की तरह उनकी आंखों से झलक दिखती थी। वो परेशान देश की स्थिति को बदलना चाहते थे। श्री मोदी ने कहा कि वो किसी एक विचार से बंधे हुए नहीं थे, खुले मन के थे। वे साम्यवादी विचार प्रभाव से अपने विद्यार्थी काल जब प्रारंभ किया बदलते-बदलते राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के समर्थक के रूप में भी अपने आप को उभारते थे। वो डरे नहीं थे, उनको चिंता नहीं हुई थी कि दुनिया क्या कहेगी। जब जो सत्य, लगा उसके लिए जी लिया, यह जयप्रकाश जी की विशेषता थी।

श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल में जिस प्रकार से संकट आए, उस प्रकार से कभी-कभी सोना तपता है, ज्यादा निखरता है। इमरजेंसी में भारत का लोकतंत्र तपा और ज्यादा निखर करके उभरा। और वो जयप्रकाश जी और उनके साथियों का जो सहयोग है उसके कारण हुआ। जुल्म के बीच भी एक जज़्बा होता है, जो मूल्यों के लिए, जीने के लिए ताकत देता है। यह आपातकाल का सबसे बड़ा सबक मिला है।

आपातकाल को याद करके रोते रहना यह मेरी प्रकृति नहीं है। आपातकाल को याद करके लोकतंत्र की ताकत को पहचानना और आने वाली पीढ़ियों को परिचित करवाना यह समय की मांग है। दुनिया और हिंदुस्तान में सब लोग मानते है, जब जेल में जनता पार्टी का मसौदा तैयार हो रहा था। सब लोग जेल में थे। एक जेल से दूसरी जेल कागज चिट्ठी, पर्चा-पार्टी जाती थी। कुछ भोजन के डिब्बे में पहुंचाई जाती थी और उसमें से वो उसका मसौदा तैयार हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत लोग थे जिनका मत था कि चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए और कुछ लोग थे, जिनका मत था कि भारत की जनता के प्रति हमारा भरोसा होना चाहिए। उसकी रगों में लोकतंत्र है। ■

सिताबदियारा

'जेपी न होते तो देश में आज भी तानाशाही होती'

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि जेपी ने लोकतंत्र को जीवंतता दी। वे न होते तो आपातकाल का खात्मा नहीं हुआ होता और आज भी राष्ट्र में तानाशाही होती। बिहार के छात्र आंदोलन की अगुवाई कर उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उस क्रांति का प्रतिफल रहा कि 1977 में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी।

आज देश में लोकतंत्र जीवित है और मजबूती के साथ खड़ा है तो उसका श्रेय जयप्रकाश नारायण को ही जाता है। लोकतंत्र में श्रद्धा रखने वालों के लिए जेपी की जन्मस्थली सिताबदियारा उनकी आस्था और विश्वास की भूमि है। वे सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें इस पावन भूमि पर आने का मौका मिला। गत 11 अक्टूबर को लोकनायक की जन्मस्थली सिताबदियारा के लाला टोला में आयोजित जेपी जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे।

श्री शाह ने कहा कि राजसत्ता पर लोकसत्ता का अंकुश की राह किसी ने बनाई तो वे जेपी थे। गांधीजी के बाद वे देश के दूसरे नेता थे, जिन्होंने सरकारी पद का त्याग किया और आजीवन रचनात्मक कार्य में लगे रहे। उन्होंने जीवनपर्यंत देश को दिया, लिया कुछ नहीं। इसके साथ उन्होंने नानाजी देशमुख को भी याद किया। कहा- आज दोनों महापुरुषों की जयंती है। इन दोनों का बड़ा सपना ग्रामोदय का था। जेपी के अनुयायी यहां सत्ता में तो रहे, लेकिन उनके सपने को भुला दिया। कहा- खुद को जेपी का अनुयायी बताने वाले नीतीश को इंदिरा गांधी की जयंती तो याद है पर वह लोकनायक की जयंती पर सिताबदियारा आना भूल गए। श्री शाह ने कहा कि अब परिवर्तन का समय आ गया है। हमें ऐसा बिहार बनाना है, जो पूरे देश को ग्रामोत्थान का मॉडल बताए। एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार बदलेगा। कश्मीर के कन्याकुमारी व कच्छ तक को यह प्रदेश ग्राम विकास की राह दिखाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल का राष्ट्रीय स्मारक बनवाया और अब जन्मस्थली लाला टोला में जेपी का राष्ट्रीय स्मारक बनवाने का फैसला किया है। ये दोनों महापुरुष किसी पार्टी के नहीं थे, राष्ट्र के थे। यहां जेपी का स्मारक जल्द ही बनेगा और यह स्मारक लोकतंत्र में आस्था रखने वालों का पूजनीय स्थल होगा। ■

लद्दाख में भाजपा की भारी विजय
स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव

पिछली संसदीय चुनाव में लेह में भाजपा ने चुनाव जीते थे, वहां इस बार लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद ने चुनाव में भारी विजय प्राप्त की है। किन्तु, कांग्रेस को भाजपा के हाथों लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथों, जिसने 18 सीटें जीती थीं, घोर पराजय का सामना करना पड़ा है, जिसमें कांग्रेस को मात्र चार सीटों ही प्राप्त हो सकी हैं। भाजपा प्रत्याशियों ने लगद, पानायिक, तंगरसे, चुशूल, कुनग्याम, शक्ति, ईगू, मात्सेलंग, थिकसे, चुचोर, ऊपरी लेह, यांग, स्कू-मरर्वा, सस्पोल, तेमिस्गाम, खालत्से और स्कुर्बुचन सीटों पर विजय प्राप्त की, जिनके चुनाव 19 अक्तूबर में हुए थे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चुनाव में विजय की सराहना कर इस क्षेत्र के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने भाजपा पर अपनी आस्था बनाए रखी हैं उन्होंने लद्दाख पर्वतीय परिषद चुनाव के परिणामों पर खुशी प्रकट की है।

उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं भाजपा पर अपनी आस्था बनाए रखने के लिए आभार प्रकट करता हूं। भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। पिछले एलएचडीसी चुनावों में कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में लेह में दोनों सीटें गंवा दी थी, जिस पर अब सभी परिषदों के चुनावों पर कब्जा कर लिया है। नेशनल कांफ्रेंस किसी तरह दो सीटें जीत पाई है जबकि स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी एक सीट प्राप्त कर ली है।

किन्तु, कांग्रेस ने भाजपा और पीडीपी दोनों को चुनाव में सरकारी मशीन का दुरूपयोग करने का आरोपी ठहराया है। उनका कहना है कि यह पीडीपी और भाजपा के बीच टैक्टीकल समझदारी थी जिससे उसने कांग्रेस से एलएचडीसी के नियंत्रण से हथिया ली हैं। राज्य भाजपा प्रवक्ता श्री अरूण गुप्ता ने कहा कि लेह के लोग विकास चाहते हैं, अत: उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों को निर्वाचित किया है। ''हमारे लिए यह भारी विजय है। देश के अन्य भागों की तरह कांग्रेस लद्दाख क्षेत्र में भी बुरी तरह विफल रही है, जिससे लोगों ने हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनना बेहतर समझा क्योंकि वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए वायदों के अनुसार आधुनिक लाइन पर क्षेत्र का विकास चाहते हैं।''

उल्लासित भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कहा कि पार्टी की विजय केवल जम्मू क्षेत्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने लद्दाख क्षेत्र के निर्जन इलाकों में भी स्वयं स्थापित किया है।

भाजपा सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा ने कहा है कि ''भाजपा ने लद्दाख में एक नया अध्याय लिखा है और इसका श्रेय नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को जाता है और यह भाजपा की विचारधारा और सिद्धांतों की विजय है। कांग्रेस और एनसी हर चुनाव में एक के बाद अपना आधार खोती चली जा रही है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि इन परिणामों से पार्टी को लेह में अपना आधार स्थापित करने में मदद मिलेगी क्योंकि सभी जिला योजनाओं एलएएचडीसी द्वारा तैयार और अनुमोदित की जाती हैं, हालांकि राज्य सरकार द्वारा धन प्रदान किया जाता है। ■

दलगत स्थिति

कुल सीट 30*

पार्टी	2015	2010
भाजपा	18	4
कांग्रेस	5	22
एनसी	2	–
निर्दलीय	1	–

*(*26 सीटों पर चुनाव हुए जबकि 4 सदस्य सरकार द्वारा नामित होते हैं)*

भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार

निर्माण क्षेत्र में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 13 अक्टूबर की एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2015 के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक (आईआईपी) के आंकड़ों और सितंबर 2015 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)- नई सीरीज के अंक से भारतीय अर्थव्यवस्था सुधार की दिशा में बढ़ रही है। 34 महीनों के बाद अगस्त 2015 की आईआईपी में छह प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

2015-16 के पहले 5 महीनों में संचयी आईआईपी वृद्धि 4.1 प्रतिशत रही जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 3 प्रतिशत वृद्धि से बेहतर है। अगस्त 2015 में निर्माण क्षेत्र 6.9 प्रतिशत की वृद्धि से औद्योगिक उत्पादन में अग्रणी बन गया है। अगस्त 2015 में अनुकूल आधार प्रभाव की मदद से निवेश और खपत मांग बढ़ने से पूंजीगत माल (21.8 प्रतिशत) और उपभोक्ता वस्तुओं (17 प्रतिशत) में दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष दर वर्ष महंगाई का असर सितंबर 2015 में अखिल भारतीय सीपीआई (मिश्रित) में नजर आया और यह 4.4 प्रतिशत बढ़ गया। जबकि अगस्त 2015 में यह 3.7 प्रतिशत था। हालांकि सितंबर 2014 के 5.6 प्रतिशत की तुलना में यह कम है। सितंबर 2015 में (3.9 प्रतिशत) उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित महंगाई सितंबर 2014 (6.2 प्रतिशत) में महंगाई से कम है।

ताजा उपलब्ध सीपीआई अंक के अनुसार महंगाई कम होगी। औद्योगिक वृद्धि के आंकड़े अर्थव्यवस्था में सुधार को दर्शाते है, जो घरेलू मांग की वजह से बढ़े हैं, जबकि विदेशी क्षेत्र में अभी भी मंदी है।

अगस्त, 2015 में औद्योगिक विकास दर 6.4 फीसदी रही

अगस्त, 2015 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) 176.9 अंक रहा, जो अगस्त 2014 के मुकाबले 6.4 फीसदी ज्यादा है। इसका अर्थ यह है कि अगस्त, 2015 में औद्योगिक विकास दर 6.4 फीसदी रही। इसी तरह वित्त वर्ष 2015-16 की अप्रैल-अगस्त अवधि में औद्योगिक विकास दर 4.1 फीसदी आंकी गई है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा अगस्त, 2015 के लिए 12 अक्टूबर को जारी किये गये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित आकलन (आधार वर्ष: 2004-05) से उपर्युक्त जानकारी मिली है। 16 स्रोत एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आईआईपी का आकलन किया जाता है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पेट्रालियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उर्वरक विभाग भी इन एजेंसियों में शामिल हैं।

अगस्त, 2015 में खनन, विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) एवं बिजली क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि दर अगस्त, 2014 के मुकाबले क्रमश: 3.8 फीसदी, 6.9 फीसदी तथा 5.6 फीसदी रही। वहीं, अप्रैल-अगस्त 2015-16 में इन तीनों क्षेत्रों यानी सेक्टरों की उत्पादन वृद्धि दर

भारत विश्व में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा

- वैश्विक मंदी और निर्यात की मांग में गिरावट के बावजूद भारत विश्व में तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा
- राजमार्गों पर सरकार के बढ़े व्यय के कारण ढांचागत क्षेत्र में अधिक धनराशि का व्यय
- मुद्रा स्फीति में भारी गिरावट
- निजी निवेश में बढ़ोतरी
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी की रूकी परियोजनाओं ने काम करना शुरू किया
- लचीली मौद्रिक नीति से अर्थव्यवस्था को फायदा
- प्रमुख सब्सिडियों पर 2012-13 में जीडीपी का 2.5 प्रतिशत व्यय था जो कम होकर 2015-16 में 1.6 प्रतिशत हुआ
- चालू वर्ष में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का संग्रह उत्साहजनक
- कर संकलन के आंकड़े अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि का अनुकूल सूचकांक
- सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के कामकाज और उन्हें लाभदायक बनाने हेतु सरकार ने सुधार के लिए निर्णायक कदम उठाये

क्रमशः 1.2, 4.6 तथा 3.2 फीसदी आंकी गई है।

अगस्त, 2015 में बुनियादी वस्तुओं (बेसिक गुड्स), पूंजीगत सामान एवं मध्यवर्ती वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि दर अगस्त, 2014 की तुलना में क्रमशः 3.4, 21.8 तथा 2.6 फीसदी रही। जहां तक टिकाऊ उपभोक्ता सामान का सवाल है, इनकी उत्पादन वृद्धि दर अगस्त, 2015 में 17.0 फीसदी रही है। इसी तरह, गैर-टिकाऊ उपभोक्ता सामान की उत्पादन वृद्धि दर अगस्त, 2015 में 0.4 फीसदी रही। कुल मिलाकर उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि दर अगस्त, 2015 के दौरान 6.8 फीसदी आंकी गई है। ■

अरुण जेटली एशिया के नंबर-1 वित्त मंत्री

भाजपानीत राजग सरकार के सरकार के वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली एशिया के नंबर वन वित्त मंत्री माना गया है। लंदन की मैगजीन 'इमर्जिंग मार्केट्स' की ओर से श्री जेटली का नाम 'फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर' एशिया पुरस्कार के लिए चुना है।

मैगजीन के एक लेख में लिखा है कि भारत में मोदी सरकार बनने के बाद 18 महीनों में देश को नई आर्थिक कामयाबी मिली है, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली भी कुछ सम्मान के पात्र हैं, भारत की वित्तीय दिशा के बारे में उनके फैसले और बेहतर प्रबंधन के बिना, भारत वह हासिल नहीं कर सकता था जो उसने पाया है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री रघुराम राजन को पिछले साल मैगजीन ने 'सेंट्रल बैंक गवर्नर ऑफ द ईयर' एशिया के सम्मान से नवाजा था। ■

प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जमा हुए 25,000 करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत खोले गये खातों में जमाराशि अब 25,000 करोड़ रुपये का भी आंकड़ा पार कर गई है। यह रकम कम लागत वाली जमाराशि के रूप में बैंकों के पास आई है। पीएमजेडीवाई के तहत जो खाते खोले जा सकते हैं, वे बेसिक बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, इन खातों में शून्य बैलेंस रह सकता है। हालांकि, यह पाया गया है कि इन खातों में अच्छी-खासी राशि जमा की गई है।

7 अक्टूबर, 2015 को इन खातों में संग्रहित कुल जमाराशि 25146.97 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू गई। बैलेंस वाले पीएमजेडीवाई खातों की संख्या भी अब बढ़कर 60 फीसदी से ज्यादा हो गई है। वहीं, दूसरी ओर शून्य बैलेंस वाले पीएमजेडीवाई खातों की संख्या घटकर 40 फीसदी से नीचे आ गई है। पीएमजेडीवाई के तहत खोले गये खातों में जमा की गई राशि में बढ़ोतरी कुछ इस प्रकार से हुई है:

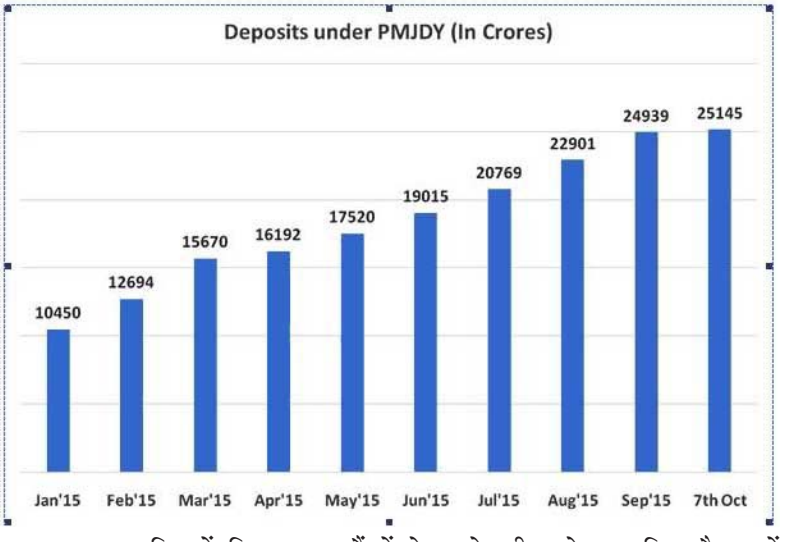

इस उपलब्धि में जिन प्रमुख बैंकों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है, उनमें भारतीय स्टेट बैंक (2989.18 करोड़ रुपये), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (2644.77 करोड़ रुपये), ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (2104.70 करोड़ रुपये), बैंक ऑफ बड़ौदा (1771.42 करोड़ रुपये) और यूको बैंक (1178.17 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

पीएमजेडीवाई - यह वित्तीय समावेश पर एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन 2014 में की थी और 28 अगस्त, 2014 को औपचारिक रूप से इसका शुभारंभ किया गया था। देश भर में सभी परिवारों को कवर करते हुए प्रति परिवार कम-से-कम एक बैंक खाता खोलना इस मिशन का मुख्य उद्देश्य रहा है। ■

प्रधानमंत्री ने डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अक्टूबर को मुंबई का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर को चैत्य भूमि में श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद इंदु मिल परिसर में डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मारक की पट्टिका का अनावरण भी किया।

करीब 400 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले स्मारक को मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पूरा करने की योजना है। संविधान के निर्माता डॉ. अंबेडकर कई साल तक इस शहर में रहे थे। आर्किटेक्ट शशि प्रभु एंड एसोसिएट्स ने 2.50 लाख वर्गफुट क्षेत्र में स्मारक बनाने का प्रस्ताव रखा है। अंबेडकर प्रतिमा 150 फुट ऊंची होगी और स्मारक पर 140 फुट ऊंचा और 110 मीटर परिधि वाला स्तूप होगा। यहां 13000 लोगों की बैठक क्षमता वाला हॉल भी बनाया जाएगा।

परियोजना में एक हिस्सा 'गैलरी ऑफ स्ट्रगल' नाम से होगा जहां अंबेडकर के जीवन और उनके कार्यों से जुड़े क्षणों को चित्रित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम से परियोजना के लिए ली गई इंदु मिल्स की करीब 7.4 हेक्टेयर जमीन पर स्मारक बनाया जाएगा। गौरतलब है कि फडणवीस सरकार ने पिछले महीने लंदन में 2050 वर्गफुट का एक बंगला भी खरीदा था जहां अंबेडकर 1921-22 में रहे थे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर का राष्ट्र के प्रति योगदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंदु मिल परिसर में एक विश्व स्तरीय स्मारक बनाया जाएगा और इस स्मारक में महाराष्ट्र के सभी गांवों की जनभागीदारी होनी चाहिए।

उन्होंने भीमराव अम्बेडकर के योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री ने आरक्षण नीति की किसी भी समीक्षा से संबंधित सभी अफवाहों का कड़े शब्दों में खंडन करते हुए कहा कि डॉ. अंबेडकर द्वारा दिए गए लाभ कोई नहीं छीन सकता। श्री मोदी ने कहा कि जब भी भाजपा की कोई सरकार सत्ता में होती है, झूठे लोगों का एक समूह दुर्भावनापूर्ण प्रचार करता है कि हम आरक्षण को खत्म करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजेपयी की सरकार के दौरान भी यही हुआ था। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि झूठी बातें बंद होनी चाहिए। समाज में आतंक पैदा करने का काम बंद होना चाहिए। यह राजनीति नहीं है।

उन्होंने कहा कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, विपक्ष आरक्षण पर बहस शुरू कर देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ऐसी चीज है जो बाबासाहेब अंबेडकर ने हमें दी है और कोई भी ताकत इसे छीन नहीं सकती। श्री मोदी ने कहा कि मैंने गरीबी देखी है। मैंने इसे जिया है। समाज के वंचित तबकों के उत्थान के लिए काफी कुछ किया

जाना बाकी है, उनकी बेहतरी के लिए बाबासाहेब प्रतिबद्ध थे। समारोह में महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सी विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी और श्री संतोष गंगवार, डॉ. अंबेडकर के पौत्र श्री प्रकाश अंबेडकर और आरपीआई नेता श्री रामदास अठावले मौजूद थे।

प्रधानमंत्री ने आधारभूत संरचनाओं की आधारशिला रखी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के चौथे कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखे जाने के अवसर पर एक पट्टिका का अनावरण किया। एक जनसभा में प्रधानमंत्री ने दो मेट्रो रेल कॉरिडोर की आधारशिला रखे जाने के अवसर पर पट्टिका का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री ने श्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु और श्री नितिन गडकरी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। उन्होंने देश के आर्थिक विकास और मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता के लिए बंदरगाहों के विकास के महत्व पर जोर दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्मदिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस से शिष्टाचार मुलाकात की। ■

नई चुनौतियों की तलाश में रहते थे डॉ. कलाम : मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अक्टूबर को पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम को 'राष्ट्रपति' से पहले 'राष्ट्र-रत्न' बताया। वह नई दिल्ली के डीआरडीओ भवन में डा. कलाम के जंयती समारोह में बोल रहे थे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए रामेश्वरम में डा. कलाम का एक स्मारक बनाया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां ज्यादातर लोग जिंदगी में अवसरों को खोजते हैं, वहीं डा. कलाम हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहते थे। उन्होंने कच्छ में भूकंप के बाद किए गए पुनर्निर्माण के दौरान डा. कलाम के साथ नजदीकी से किए काम को याद किया।

एक शिक्षक के रूप में याद किए जाने की डा. कलाम की इच्छा को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति भविष्य की पीढ़ियों के पोषण के महत्व से अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन्होंने कहा कि डा. कलाम की जंयती पर हमें यह पता लगाना चाहिए कि हम भारत में नवाचार को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कई ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का उल्लेख किया जहां नवाचार जरूरी है। इनमें साइबर सुरक्षा, सभी के लिए आवास, नदियों को जोड़ना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) और शून्य दोष, शून्य प्रभाव (जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट) वाला निर्माण शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि डा. कलाम न केवल एक बेहद सामान्य पृष्ठभूमि से भारत के सर्वोच्च पद तक पहुंचे, बल्कि वस्तुत: साधारण से असाधारण संस्थाओं का निर्माण किया। हम सभी को उनके उदाहरण से प्रेरणा लेते रहनी चाहिए।

इससे पहले प्रधानमंत्री ने डीआरडीओ भवन में डा. एपीजे अब्दुल कलाम की एक प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने 'डा. कलाम का जीवन उत्सव' शीर्षक वाली एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और उसे देखा। प्रधानमंत्री ने डा. कलाम पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया।

इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री एम वेंकैया नायडू, श्री मनोहर पर्रिकर, श्री रवि शंकर प्रसाद और डा. हर्षवर्धन उपस्थित थे। ■

जीवन का ध्येय

– दीनदयाल उपाध्याय

दीननदयालजी विचारक राजनेता थे। प्रस्तुत लेख उन्होंने 'पांचजन्य' में भाद्रपद कृष्ण १, वि. स. 2006 को लिखा था। इसमें उन्होंने बताया है कि जब तक भारत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करता तब तक विश्व की प्रगति में सहायक नहीं हो सकता। न तो वह जीवन के सत्य का साक्षात्कार कर सकेगा और न ही मानव की स्वतंत्रता का। हम यहां इस लेख का अंतिम भाग प्रकाशित कर रहे हैं:

हमारी स्वतंत्रता

ऐसी दशा में उस राष्ट्र के घटकों का प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि विजेता राष्ट्र के प्रभुत्व को नष्ट करके अपने राष्ट्र को स्वतंत्र किया जाए। उस राष्ट्र की संपूर्ण शक्ति विदेशी राष्ट्र के प्रति विद्रोह की भावना लेकर खड़ी हो जाती है और अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार अवसर प्राप्त होने पर स्वतंत्रता को प्राप्त करती है। विश्व के इस नियम के अनुसार भारतवर्ष ने भी अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध बगावत का झंडा खड़ा किया और अंत में एक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ही ली।

15 अगस्त, 1947 को हमने एक मोरचा जीत लिया। हमारे देश से अंग्रेजी राज्य विदा हो गया। उस राज्य के कारण हमारी प्रतिभा के विकास में जो बाधाएँ उपस्थित की जा रही थीं, उनका कारण हट गया, हम अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र हो गए। अपनी आत्मानुभूति का मार्ग खुल गया। किंतु अभी भी मानव की प्रगति में हमको सहायता करनी है। मानव द्वारा छेड़े गए युद्ध में जिन-जिन शस्त्रास्त्रों का प्रयोग हमने अब तक किया है, जिनके चलाने में हम निपुण हैं तथा जिन पर पिछली सहस्राब्दियों में जंग लग गई थी उन्हें पुन: तीक्ष्ण करना है तथा अपने युद्ध कौशल का परिचय देकर मानव को विजय बनाना है। आज यदि हमारे मन में उन पद्धतियों के विषय में ही मोह पैदा हो जाए, जिनके पुरूस्कर्ताओं से हम अब तक लड़ते रहे हैं तो यही कहना होगा कि हम न तो स्वतंत्रता का सच्चा स्वरूप समझ पाए हैं और न अपने जीवन के ध्येय को ही पहचान पाए हैं। हमारी आत्मा ने अंग्रेजी राज्य के प्रति विद्रोह केवल इसलिए नहीं किया कि दिल्ली में बैठकर राज्य करनेवाला एक अंग्रेज था, अपितु इसलिए भी कि हमारे दिन-प्रतिदिन के जीवन में हमारे जीवन की गति में विदेशी पद्धतियाँ और रीति-रिवाज विदेशी दृष्टिकोण और आदर्श अडंगा लगा रहे थे, हमारे संपूर्ण वातावरण को दूषित कर रहे थे, हमारे लिए साँस लेना भी दूभर हो गया था। आज यदि दिल्ली का शासनकर्ता अंग्रेज के स्थान पर हममें से ही एक, हमारे ही रक्त और माँस का एक अंश हो गया है तो हमको इसका हर्ष है, संतोष है। किंतु हम चाहते हैं कि उनकी भावनाएँ और कामनाएँ भी हमारी भावनाएँ और कामनाएँ हों। जिस देश की मिट्टी से उसका शरीर बना है, उसके प्रत्येक रजकण का इतिहास उसके शरीर के कण-कण से प्रति ध्वनित होना चाहिए। तीस कोटि के हृदयों को समष्टिगत भावनाओं से उसका हृदय उद्वेलित होना चाहिए तथा उनके जीवन के विकासक अनुकूल, उनकी प्रकृति और स्वभाव अनुसार तथा उनकी भावनाओं और कामनाओं के अनुरूप पद्धतियों की सृष्टि उसके द्वारा होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो हमको कहना होगा कि अभी भी स्वतंत्रता की लड़ाई बाकी है। अभी हम अपनी आत्मानुभूति में आनेवाली बाधाओं को

दूर नहीं कर पाए हैं।

सब प्रकार स्वतंत्र हों

अंग्रेजी राज्य के चले जाने के बाद आवश्यक है कि हमारा देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में भी स्वतंत्रता का अनुभव करें। जब तक भारतवर्ष आर्थिक दृष्टि से परमुखापेक्षी है तथा भारत को तीस कोटि संतान की आर्थिक उन्नति का समान अवसर प्राप्त नहीं है, जब तक उनकी उन्नति के द्वार खुले नहीं हैं तथा उसके साधन प्रस्तुत नहीं हैं, तब तक भारतवर्ष विश्व की प्रगति में कदापि सहायक नहीं हो सकता। न तो वह जीवन के सत्य का साक्षात्कार कर सकेगा और न मानव की स्वतंत्रता का ही।

आर्थिक स्वाधीनता के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की भी आवश्यकता है। आत्मानुभूति के प्रयत्नों में जिन सामाजिक व्यवस्थाओं एवं पद्धतियों की राष्ट्र अपनी सहायता के लिए सृष्टि करता है अथवा जिन रीति-रिवाजों में उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, वे ही यदि कालानुपात से उसके मार्ग में बाधक होकर उसके ऊपर भार रूप हो जाएँ तो उनसे मुक्ति पाना भी प्रत्येक राष्ट्र के लिए आवश्यक है। यात्रा की एक मंजिल में जो साधन उपयोगी सिद्ध हुए हैं वे दूसरी मंजिल में भी उपयोगी सिद्ध होंगे यह आवश्यक नहीं। साधन तो प्रत्येक मंजिल के अनुरूप ही चाहिए तथा इस प्रकार प्रयाण करते हुए प्राचीन साधनों का मोह परतंत्रता का ही कारण हो सकता है क्योंकि स्वतंत्रता केवल उन तंत्रों का समष्टिगत नाम है जो स्वानुभूति में सहायक होते हैं।

सांस्कृतिक स्वतंत्रता

राष्ट्र की सांस्कृतिक स्वतंत्रता तो

आर्थिक स्वाधीनता के साथ-साथ सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की भी आवश्यकता है। आत्मानुभूति के प्रयत्नों में जिन सामाजिक व्यवस्थाओं एवं पद्धतियों की राष्ट्र अपनी सहायता के लिए सृष्टि करता है अथवा जिन रीति-रिवाजों में उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति होती है, वे ही यदि कालानुपात से उसके मार्ग में बाधक होकर उसके ऊपर भार रूप हो जाएँ तो उनसे मुक्ति पाना भी प्रत्येक राष्ट्र के लिए आवश्यक है।

अत्यंत महत्त्व की है, क्योंकि संस्कृति ही राष्ट्र के संपूर्ण शरीर में प्राणों के समान संचार करती है। प्रकृति के तत्त्वों पर विलय पाने के प्रयत्न में तथा मानवानुभूति की कल्पना में मानव जिस जीवन दृष्टि की रचना करता है वह उसकी संस्कृति है। संस्कृति कभी गतिहीन नहीं होती अपितु वह निरंतर गतिशील होती है फिर भी उसका अपना एक अस्तित्व है। नदी के प्रवाह की भाँति निरंतर गतिशील होते हुए भी वह अपनी निजी विशेषताएँ रखती हैं जो उस सांस्कृतिक दृष्टिकोण को उत्पन्न करनेवाले समाज के संस्कारों में तथा उस सांस्कृतिक भावना से जन्य राष्ट्र के साहित्य, कला, दर्शन, स्मृति शास्त्र, समाज रचना इतिहास एवं सभ्यता के विभिन्न अंग अंगों में व्यक्त होती हैं। परतंत्रता के काल में इन सब पर प्रभाव पड़ जाता है तथा स्वाभाविक प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। आज स्वतंत्र होने पर आवश्यक है कि हमारे प्रवाह की संपूर्ण बाधाएँ दूर हों तथा हम अपनी प्रतिभा अनुरूप राष्ट्र के संपूर्ण क्षेत्रों में विकास कर सकें। राष्ट्र भक्ति की भावना को निर्माण करने और उसको साकार स्वरूप देने का श्रेय भी राष्ट्र की संस्कृति को ही है तथा वही राष्ट्र की संकुचित सीमाओं को तोड़कर मानव की एकात्मता का अनुभव कराती है। अत: संस्कृति की स्वतंत्रता परमावश्यक है। बिना उसके राष्ट्र की स्वतंत्रता निरर्थक ही नहीं, टिकाऊ भी नहीं रह सकेगी।

स्वार्थ का साधन नहीं

आज अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता का उत्सव मनाते समय हम स्वतंत्रता के इन मूल्यों को समझें। स्वतंत्रता को कुछ व्यक्ति समूह के स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाना, फिर वह व्यक्ति समूह तीस करोड़ का ही क्यों न हो, स्वतंत्रता को उसके महान् आसन से गिराकर धूल में मिलाना होगा। इस प्रकार के दृष्टिकोण से कार्य करने पर न तो स्वतंत्रता की हम अनुभूति ही कर पाएँगे और न हम विश्व को ही कुछ सेवा कर पाएँगे। अपितु इस प्रकार का स्वार्थी और अहंकारी भाव लेकर कार्य करने पर हम उसी इतिहास की पुनरावृत्ति करेंगे जो कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर प्रभाव जमाने में निर्माण करता है। यहाँ पात्र भिन्न होंगे, वे एक ही राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर प्रभाव जमाने में निर्माण करता है। यहाँ पात्र भिन्न होंगे, वे एक ही राष्ट्र के घटक होंगे, पास-पास रहनेवाले पड़ोसी होंगे और इसलिए उनके कृत्य और भी भयंकर हो जाते हैं तथा उसका परिणाम भी सर्वव्यापी विनाश हो सकता है। किंतु हमारा विश्वास है कि राष्ट्र की जीवनदायिनी शक्ति अपने सच्चे स्वरूप और कार्य को समझेगी तथा विनाश के स्थान पर विकास के मार्ग पर अग्रसर होती हुई भारत की तीस कोटि संतान अपने परम लक्ष्य परब्रह्म की प्राप्ति तथा विश्वात्मा की अनुभूति कराएगी। ■

बिहार विधानसभा चुनाव पर विशेष

पांच चरणों में संपन्न होनेवाले बिहार विधानसभा चुनाव में दो चरण संपन्न हो चुके हैं। भारी संख्या में मतदाता मतदान कर रहे हैं। ऐसा लगता है, लोगों ने सत्ता परिवर्तन का मन बना लिया है। हर तरफ भाजपानीत राजग के पक्ष में लहर है। मतदाता जात-पात से ऊपर उठकर इस बार विकास के लिए वोट डाल रहे हैं। विदित हो कि 12 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच चुनाव होने हैं और वोटों की गिनती 8 नवंबर को होगी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह एवं पार्टी के वरिष्ठ नेतागण लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। प्रस्तुत है संक्षिप्त समाचार :

मेसकौर, हसपुर और समस्तीपुर रैली

यदि राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो सम्पूर्ण गौ-वंश की हत्या को राज्य में प्रतिबंधित किया जाएगा : अमित शाह

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने 9 अक्तूबर को बिहार के नवादा के मेसकौर, औरंगाबाद के हसपुर और समस्तीपुर की रैली में विशाल जन-समुदाय को सम्बोधित किया और इस बार के बिहार विधान सभा चुनाव में जनता से राज्य में दो तिहाई की बहुमत से भाजपा की अगुआई में राजग सरकार बनाने की अपील की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार के विकास के लिए 1 लाख 65 करोड़ का विशेष पैकेज दिया है, यह पैकेज गाँवों को सड़कों से जोड़ेगा, खेतों में

सिंचाई के लिए समुचित पानी की व्यवस्था करेगा, बिहार के युवाओं के लिए रोजगार का सृजन करेगा, गरीब और उपेक्षित लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करेगा और राज्य में उद्योग-कारखानों के साथ-साथ राज्य के बुनियादी ढाँचे के तंत्र को मजबूत करेगा। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिया गया विशेष पैकेज बिहार सरकार के तीन साल के बजट के बराबर है और यह पैकेज बिहार के विकास के लिए है। उन्होंने कहा कि श्री नीतीश कुमार को कोई अधिकार नहीं है कि वह बिहार की जनता को उनके विकास से महरूम रखे। उन्होंने कहा कि यह कितना हास्यास्पद है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सवा लाख करोड़ रुपये के विशेष पैकेज पर श्री नीतीश कुमार कटाक्ष कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि ये पैकेज उनके लिए नहीं, बिहार के विकास के लिए है। श्री शाह ने कहा कि सत्ता के स्वार्थ के लिए किया गया कांग्रेस, राजद और जद(यू) का गठबंधन प्रधानमंत्री जी द्वारा राज्य के विकास और उसकी समृद्धि के लिए दिए गए पैकेज को सही तरीके से लागू कर पाएगी, इसमें संदेह है। उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि आज बिहार के युवाओं को पढ़ाई और रोजगार के लिए बिहार से पलायन करना पड़ रहा है, हमें इस स्थिति को बदलना है। उन्होंने कहा कि राज्य में एक ऐसी सरकार चाहिए जो केंद्र से कंधे-से-कंधा मिलाकर विकास के पथ पर आगे बढ़े और ऐसा केवल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा की अगुआई वाली राजग सरकार ही कर सकती है। श्री शाह ने कहा कि बिहार में हम ऐसी लोक-कल्याणकारी सरकार की स्थापना करना चाहते हैं जो बिहार के गाँवों का विकास कर सके, जो राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित कर सके, युवाओं के लिए राज्य में रोजगारों का निर्माण कर सके और विकास में पिछड़ गए गरीबों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों और वंचितों का समुचित विकास कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल कर सके।

श्री शाह ने श्री लालू यादव पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता लालू के जी 15 साल के जंगलराज को याद कर आज भी सिहर उठती है। उन्होंने कहा कि श्री लालू जी का विकास और समाजवाद, परिवारवाद पर सिमट कर रह गया है। श्री शाह ने कहा कि महागठबंधन ने बेटे बेटियों की सरकार चलाई, हमने हर जगह गरीबों और पिछड़ों के उत्थान की सरकार चलाई है। उन्होंने कहा कि श्री लालू जी का पूरा ध्यान अपने परिवार के विकास पर केंद्रित है, जबकि भाजपा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास' की परिकल्पना के आधार पर सबका विकास चाहती है। उन्होंने कहा कि लालू जी राज्य के विकास की बात करने के बजाय उलूल-जुलूल बोलते रहते हैं, वह बिहार के गरीब, दलित, महादलित और पिछड़े वर्ग के कल्याण की बात क्यों नहीं करते, वह राज्य में बिजली की स्थिति पर बात क्यों नहीं करते, सड़कों पर बात क्यों नहीं करते, स्कूलों और कॉलेजों की बात क्यों नहीं करते, अस्पतालों और चिकित्सकों की बात क्यों नहीं करते, वह प्रदेश के विकास और रोजगार की बात क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा कि कभी लालू जी कौवों-चूहों और गौ-मांस को लेकर विवादित बयान देते हैं, कभी उन्हीं की पार्टी के रघुवंश बाबू हमारे ऋषि-मुनियों को लेकर अनाप-शनाप बोलते हैं, बिहार की जनता को ऐसे कुत्सित सोच वाले राजनेता कदापि स्वीकार्य नहीं हो सकते, उन्हें राज्य का विकास करने वाले, राज्य के गरीबों और पिछड़ों का कल्याण करनेवाले राजनेताओं की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में भाजपा की सरकार बनती है तो सम्पूर्ण गौ-वंश की हत्या को राज्य में प्रतिबंधित किया जाएगा।

भाजपा अध्यक्ष श्री शाह ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जनता से अपील की कि वह राजग को विजयी बनाने के लिए ऐसे बटन दबाए कि इटली तक करंट दौड़ जाए।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ विकासराज का एकजुट राजग गठबंधन है तो दूसरी तरफ किसी भी तरह से राज्य की सत्ता पर काबिज होने की फिराक में किया गया महास्वार्थबंधन। उन्होंने कहा कि श्री नीतीश कुमार के एक कंधे पर तो जंगलराज और अपराध के प्रतीक श्री लालू यादव हैं तो दूसरे कंधे पर 12 लाख करोड़ रुपये का घपला करनेवाली कांग्रेस, ऐसे में भला उनसे राज्य के विकास की आशा कैसे की जा सकती है? श्री शाह ने कहा कि बिहार को श्री लालू प्रसाद यादव के जंगलराज से मुक्ति दिलाने के लिए ही राज्य की जनता ने उन्हें भाजपा के साथ अपना जनादेश दिया था और भाजपा ने उन्हें राज्य के सत्ता की बागडोर सौंपी थी, लेकिन 20 वर्षों तक लगातार लालू जी के जंगलराज के विरोध की राजनीति करने वाले श्री नीतीश कुमार आज फिर केवल सत्ता का सुख भोगने के उद्देश्य से श्री लालू जी के जंगलराज के साथ समझौता कर बिहार के विकास को दाव पर लगा दिया। श्री शाह ने कहा कि लालू जी के शासन को जंगलराज का नाम हमने नहीं, श्री नीतीश कुमार ने दिया था, आज सत्ता-सुख के लिए वह उन्हीं लालू जी के साथ चल रहे हैं, यह कैसा विरोधाभास है? उन्होंने कहा कि आखिर बिहार की जनता उनपर विकास का विश्वास कैसे करे? श्री शाह ने कहा कि बिहार का विकास प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव है।

श्री शाह ने श्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा

शेष पृष्ठ 30 पर

बक्सर/पालीगंज/आरा/सीवान.

नीतीश राज में स्कूल के बदले खुलीं शराब की दुकानें

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह ने कहा कि नीतीश पहले लालू के खिलाफ थे, आज दोस्ती कर लिए हैं। उनके राज में स्कूल के बदले शराब की दुकानें खुली हैं। 25 वर्षों में लालू व नीतीश ने बिहार को बर्बाद कर दिया। बिहार के नवनिर्माण के लिए एनडीए की सरकार बनानी जरूरी है। यदि एनडीए की सरकार बनी तो बिहार में विकास के नए इतिहास की शुरुआत होगी।

उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लाख 65 हजार करोड़ रुपए दिए हैं, उस पर भी नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं। आज अस्पताल में दवा नहीं है। स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही, फिर भी नीतीश कुमार सुशासन का दावा कर रहे हैं। आपराधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। एसपी को अपराधी गोली मार रहे हैं। जब एसपी सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोगों की क्या हालत होगी? वे भाजपा पर आरक्षण का विरोध करने का दुष्प्रचार कर रहे हैं। पर, भाजपा ऐसा कभी नहीं कर सकती। मौके पर भाजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगल पांडेय, सांसद श्री अश्विनी कुमार चौबे, प्रत्याशी श्री विवेक ठाकुर भी थे।

जहानाबाद और भभुआ रैली

बिहार की बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार का जाना तय है : नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 12 अक्तूबर को बिहार के जहानाबाद और भभुआ में विशाल रैलियों को सम्बोधित किया और राज्य की जनता से बिहार से भ्रष्टाचार, जंगलराज और कुशासन की सरकार को जड़ से उखाड़ कर राज्य में भाजपा को प्रचंड बहुमत देकर भारतीय जनता पार्टी की अगुआई में दो-तिहाई बहुमत की विकास की राजग सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने निर्बाध रूप से मतदान का बेहतर इंतजाम करने के लिए निर्वाचन आयोग को बधाई भी दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आपका अविरल प्यार और आशीर्वाद, पग-पग पर मेरा बिहार का विकास करने के लिए हौसला बढ़ा रहा है और विकास में रोड़ा अटकाने वालों को बेचैन कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुझ पर आपका हक बनता है और मैं आपका प्यार बिहार का विकास करके ब्याज समेत आपको लौटाऊंगा। उन्होंने कहा कि बिहार की बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार का जाना तय है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता विकास के लिए मतदान कर रही है।

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मोदी को रोकने के लिए दिन-पर-दिन नए षड़यंत्र किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझको जनता से मिल रहे अपार समर्थन से महास्वार्थबंधन के नेता इतने डर गये हैं कि वह मेरे सभाओं को भी रोकने की ओछी राजनीति पर उतर आये हैं। उन्होंने कहा कि इसी तरह मेरे 'मन की बात' कार्यक्रम को भी रोकने की कोशिश की गई थी, मेरी आज की सभा को भी रोकने का प्रयास किया गया, इतना ही नहीं, टीवी पर उसे नहीं दिखाने के भी हथकंडे अपनाये गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सरकारें समझ लें, आप मोदी को तो रोक सकते हैं लेकिन आप जनता के प्यार और आशीर्वाद को नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में

संबोधन के मुख्य अंश

- इस बार बिहार की जनता विकास के लिए मतदान कर रही है।
- हमारा एजेंडा बिहार का विकास है।
- बिहार हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बने, यही मेरा सपना है।
- बिहार को ऐसी सरकार चाहिए जिसे बिहार की चिंता हो, जो बिहार की भलाई के लिए काम करे।
- सरकारें समझ लें, आप मोदी को तो रोक सकते हैं लेकिन आप जनता के प्यार और आशीर्वाद को नहीं रोक सकते।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गरीबों, पिछड़ों और दलितों के जीवन-स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम साबित हो रही है।
- लोकतंत्र में आप किसी की आवाज नहीं दबा सकते।
- लोकनायक के जन्म दिवस पर उनका ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ।
- हमारा नौजवान मिट्टी से सोना पैदा करने की ताकत रखता है।
- पूरा राजग एकजुट होकर बिहार के विकास के लिए हमें मौका दिए जाने की बात करता है जबकि स्वार्थबंधन के नेता केवल मोदी के विनाश की बात करते हैं।
- बिहार सरकार पैसों के बावजूद न तो योजना बना सकती है और न ही काम कर सकती है, बस राजनीति कर सकती है, क्या ऐसी सरकार बिहार का विकास कर सकती है।
- हमें बिहार में 24 घंटे बिजली पहुंचानी है।
- बिहार अपनी ताकत - अपनी पानी और अपनी जवानी का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है।
- बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर गरीबों के नाम पर बिहार को तबाह करके रख दिया है।
- केंद्र की वर्तमान राजग सरकार देश के किसानों की भलाई के लिए कटिबद्ध है।
- निर्बाध रूप से मतदान का बेहतर इंतजाम करने के लिए निर्वाचन आयोग को बधाई।
- जो लोग बिहार की जनता से धोखा करते हों, उन्हें मूर्ख समझने की भूल करते हों, बिहार की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी।

आप किसी की आवाज नहीं दबा सकते।

प्रधानमंत्री ने निर्वाचन आयोग से विशेष आग्रह करते हुए कहा कि मुझे भभुआ और जहानाबाद के इलाके से साजिश की बू आ रही है, इस क्षेत्र में मतदान तक विशेष निगरानी रखी जाये। उन्होंने इस क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि आप घर- घर जाकर मतदान के अधिकार का उपयोग करने का अलख जगाइये और पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मतदान का रिकार्ड तोड़िये, मेरे खिलाफ षड्यंत्र करनेवालों को मेरा यही जवाब होगा।

अवधेश कुशवाहा के स्टिंग पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कि पूरे हिंदुस्तान ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प करके मनाई, लेकिन उनके तथाकथित अनुयायी चार लाख रुपये का रिश्वत लेते पकड़े गये। उन्होंने कहा कि लोकनायक के जन्म दिवस पर उनका ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि स्टिंग में वर्तमान बिहार सरकार के पांच मंत्रियों तक भी पैसा पहुंचाने की बात की गई है, वर्तमान बिहार सरकार को इसे सार्वजनिक करना चाहिए। श्री नीतीश कुमार के श्री लालू यादव के साथ किये गये स्वार्थबंधन पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे ही वे नए जोड़ीदार के पास गए, वैसे ही उनके कारनामें बदलने लगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार में रहते हुए ऐसी बोली लगाई जाएगी तो राज्य की आम जनता कैसे खुशहाल होगी?

प्रधानमंत्री ने जंगलराज पर निशाना साधते हुए कहा कि इस चुनाव में एक तरफ तो 60 सालों तक का बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार और जंगलराज का शासन करनेवाली महास्वार्थबंधन है, जिन्हें अपने कारनामों का हिसाब देना चाहिए तो दूसरी तरफ विकास के पथ को अपना सिद्धांत मानकर चलनेवाली राजग का गठबंधन है जो बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पूरा राजग एकजुट होकर बिहार के विकास के लिए हमें मौका दिए जाने की बात करता है जबकि स्वार्थबंधन के नेता केवल मोदी के विनाश की बात करते हैं, इसके सिवा उनके पास कोई काम ही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय बिहार की जनता को करना है कि उन्हें बिहार के विकास के लिए वोट करना है या नहीं? श्री मोदी ने कहा कि जंगलराज का एक ही उद्योग था - अपहरण, अवैध खनन और माफियागिरी। उन्होंने कहा कि महास्वार्थबंधन के घटक दलों की राज्य सरकारों ने बिहार के प्राकृतिक संशाधनों को लूटने का काम किया है और बिहार की जनता इस बार के चुनाव में ऐसे लोगों को माकूल जवाब देगी। उन्होंने कहा कि हमारा एजेंडा सिर्फ बिहार का विकास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी ताकत बने, यही मेरा सपना है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि मैं आज बिहार की धरती पर यहां के मुख्यमंत्री और लालू जी से प्रश्न पूछता हूं कि आप ऐसी कांग्रेस के साथ कैसे बैठ सकते हो, जिन्होंने दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज को हमेशा से दबाने का काम किया?

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि मैं बिहार के लोगों से प्रार्थना करने आया हूं कि बिहार और दिल्ली आपस में लड़ते रहें - क्या यह स्थिति ठीक है? इसके चलते हमारे 30 साल बर्बाद हुए। पहली बार मौका आया है कि हम दिल्ली से कंधे-से-कंधा मिलाकर बिहार में विकास की बयार लानेवाली सरकार का चुनाव करें। अब बिहार को ऐसी सरकार चाहिए, जो गरीब, पिछड़ों और दलितों के कल्याण की जिम्मेदारी ले और उसका हिसाब दे।

बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के विकास के खोखले दावे पर कड़ा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा में दिए गए 1000 करोड़ का हिसाब नहीं दिया है। स्वास्थ्य मद के लिए दी गई राशि में से 500 करोड़ का भी हिसाब नहीं दिया है। पिछड़े वर्ग और गरीब छात्राओं के पैसों में से 300 करोड़ का हिसाब दिल्ली सरकार को नहीं दिया गया। दिल्ली से विकास के लिए राशि तो आये, लेकिन यहां की सरकार ही यदि हिसाब देने की स्थिति में नहीं हो तो बिहार में तरक्की कैसे संभव है?

प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के लिए पिछले वर्ष केंद्र

सरकार ने नौ हजार एक सौ करोड़ रुपये की राशि जो बिहार सरकार को दी थी, उसमें से पांच हजार करोड़ रुपये अभी तक बैंक में ही पड़े हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की सरकार दिल्ली से बिहार के विकास के लिए दिये गये पैसों का या तो हिसाब नहीं देती या उसे बिहार के लोगों की भलाई में ही नहीं लगाती। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार पैसों के बावजूद न तो योजना बना सकती है और न काम कर सकती है, बस राजनीति करती है, क्या ऐसी सरकार बिहार का विकास कर सकती है?

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र सरकार द्वारा बिहार को ध्यान में रखकर शुरू की गयी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमने बिहार में सड़कों के निर्माण के लिए, उद्योग-धंधों की स्थापना के लिए, राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, रोजगार का सृजन करने के लिए एवं विकास में पिछड़ गए लोगों के कल्याण के लिए हमने बिहार को 1.65 लाख करोड़ रुपये का विशेष पैकेज दिया है जो बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर करेगा।

उन्होंने कहा कि 13 हजार करोड़ रुपये की लागत से 22 हजार किलोमीटर लंबी सड़कें बिछाने का हमने निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि हमारा नौजवान मिट्टी से सोना पैदा करने की ताकत रखता है और उन्हें बस तलाश है उचित अवसर की। श्री मोदी ने कहा कि हमने बिहार के युवाओं के कौशल विकास के लिए 1500 करोड़ रुपये की राशि दी है ताकि बिहार का युवा राष्ट्र-निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभा सके। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि केंद्र की वर्तमान राजग सरकार देश के किसानों की भलाई के लिए कटिबद्ध है और हमने बिहार के किसानों के कल्याण के लिए 3000 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के 68 साल बाद भी देश की 60 प्रतिशत आबादी के पास अपना बैंक खाता तक नहीं था, हमारी सरकार ने एक वर्ष के ही अंदर गरीबों के लिए बैंकों के दरवाजे खोल दिए। श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि अकेले बिहार में तीन लाख से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं और यह योजना गरीबों, पिछड़ों और दलितों के जीवन-स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम साबित हो रही है।

बिहार में फसलों के अपेक्षाकृत कम पैदावार पर बोलते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि 25 साल तक बड़े भाई-छोटे भाई ने मिलकर बिहार में सरकार चलाई लेकिन बिहार का विकास नहीं किया। उन्होंने कहा कि बिहार प्रति हेक्टेयर गेहूं और धान की पैदावार देश में प्रति हेक्टेयर उपज की अपेक्षा काफी कम है और इसके कारण बिहार के किसानों को काफी घाटा उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों का विकास करना नहीं चाहती। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह बिहार में कृषि की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कृतसंकल्प हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बिहार अपनी ताकत - अपनी पानी और अपनी जवानी का सदुपयोग नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें बिहार का पानी भी बचाना है, बिहार की जवानी भी बचानी है, बिहार को आगे भी बढ़ाना है एवं बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाना है।

बिहार में 2015 तक बिजली देने के श्री नीतीश कुमार के झूठे दावे पर तंज करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार की जनता के साथ धोखा किया है, तिस पर वह यह कह रहें हैं कि मैंने ऐसा कोई वादा ही नहीं किया था। श्री मोदी ने कहा कि जो लोग बिहार की जनता से धोखा करते हों, उन्हें मूर्ख समझने की भूल करते हों, बिहार की जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें बिहार में 24 घंटे बिजली पहुंचानी है। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश के 18000 गाँवों तक अभी बिजली नहीं पहुँची है जिसमें से अकेले बिहार में ही ऐसे 4000 गाँव हैं जो अभी भी बिजली से महरूम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष से राज्य की सत्ता पर काबिज बड़े भाई और छोटे भाई की सरकार ने राज्य में बिजली की स्थिति को सुधारने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पहले मतदान, फिर जलपान का नारा देते हुए सभी से मतदान के अधिकार का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बिहार को ऐसी सरकार चाहिए जिसे बिहार की चिंता हो, जो बिहार की भलाई के लिए काम करे। प्रधानमंत्री ने जनता का आह्वान करते हुए कहा कि इस बार के बिहार विधान सभा चुनाव में आप मतदान के जरिये, 25 साल तक बिहार को बर्बाद कर देने वाले बड़े भाई-छोटे भाई के कारनामों की उन्हें सजा दीजिये, एक दलित के बेटे का अपमान करने की उन्हें सजा दीजिये और भाजपा की अगुआई में बिहार में विकास की बयार लाने वाली राजग सरकार का चुनाव करिये। ■

एनजेएसी पर अदालत का निर्णय – एक वैकल्पिक दृष्टिकोण

–अरुण जेटली

भारत की सर्वोच्च अदालत ने बहुमत से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना हेतु किये गए 99 वें संविधान संशोधन को खारिज कर दिया। पांच माननीय न्यायाधीशों की राय पढ़ने के बाद, मेरे दिमाग में कुछ मुद्दे उत्पन्न होते हैं।

बहुमत की राय के पीछे के मुख्य तर्क से यह प्रतीत होता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का एक अनिवार्य अंग है। निश्चित रूप से यह एक सही प्रस्ताव है। ऐसा कह कर बहुमत एक त्रुटिपूर्ण तर्क में अतिक्रमण कर रही है। इनका तर्क है कि आयोग में कानून मंत्री की उपस्थिति और दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति, जिनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा, प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होंगे, न्यायिक नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप को संस्थापित करेगा। इस आधार पर नियुक्त न्यायाधीश राजनेताओं के प्रति आभार महसूस कर सकते हैं। एक राजनीतिक व्यक्ति स्पष्ट रूप से अपने राजनीतिक हित के द्वारा निर्देशित किया जाएगा। न्यायाधीशों ने 'प्रतिकूल' परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है अगर राजनेता नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। इसलिए न्यायपालिका की राजनीतिक व्यक्तियों से सुरक्षा आवश्यक थी। यही प्रमुख कारण है जिसके चलते सर्वसम्मति से संसद और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन को खारिज किया गया है।

यह फैसला भारत के बृहत् संवैधानिक संरचना को अनदेखा करती है। निर्विवाद रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है। इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन यह निर्णय इस तथ्य के ओर ध्यान नहीं देता कि संविधान की कई अन्य विशेषताएं हैं जो बुनियादी संरचना में शामिल है। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संसदीय लोकतंत्र है।

इस निर्णय का मुख्य पहलू राजनेताओं को कोसना है। एक समझदार न्यायाधीश तर्क देते हैं कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी का विचार है कि किसी आपातकालीन जैसी स्थिति के खतरे अभी भी हैं। भारत में सिविल सोसायटी मजबूत नहीं है और इसीलिये, आपको एक स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत है। दूसरे तर्क देते हैं कि यह संभव है कि वर्तमान सरकार उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में वैकल्पिक लैंगिकता वाले वक्तियों की नियुक्ति के पक्ष में नहीं है। राजनेताओं को कोसना टेलीविजन के प्राइम टाइम कार्यक्रमों का पर्याय बन चुका है ।

यह फैसला भारत के बृहत् संवैधानिक संरचना को अनदेखा करती है। निर्विवाद रूप से न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है। इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन यह निर्णय इस तथ्य के ओर ध्यान नहीं देता कि संविधान की कई अन्य विशेषताएं हैं जो बुनियादी संरचना में शामिल है। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संसदीय लोकतंत्र है। भारतीय संविधान की अगली महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना एक चुनी हुई सरकार है जो देश की संप्रभुता की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती है। प्रधानमंत्री संसदीय लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण जवाबदेह संस्था है। विपक्ष के नेता बुनियादी संरचना का एक अनिवार्य पहलू हैं जो संसद में वैकल्पिक आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। कानून मंत्री संविधान संविधान की एक प्रमुख बुनियादी संरचना, मंत्रिपरिषद, का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संसद के प्रति जवाबदेह है। ये सभी संस्थाएं, संसदीय संप्रभुता, एक निर्वाचित सरकार, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, कानून मंत्री संविधान के बुनियादी ढांचे का एक हिस्सा हैं। वे लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाहिर है कि

बहुमत की राय का वास्ता एकमात्र बुनियादी संरचना से था – न्यायपालिका की स्वतंत्रता – जबकि एक तर्क के औचित्य पर निर्णय पारित करके कि भारत के लोकतंत्र को उसके चुने हुए प्रतिनिधियों से बचाना है, अन्य सभी बुनियादी संरचनाओं को 'राजनेता' के रूप में जिक्र कर निरर्थक बता दिया गया। न्यायाधीशों के निर्णय ने एक बुनियादी संरचना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता की श्रेष्ठता को बरकरार रखा है लेकिन संविधान के पांच अन्य बुनियादी ढांचे, संसदीय लोकतंत्र, चुनी हुई सरकार, मंत्रि परिषद, एक निर्वाचित प्रधानमंत्री और चुने हुए विपक्ष के नेता को कमजोर कर दिया है। बेंच के बहुमत ने यह बुनियादी गलती की है। एक संवैधानिक अदालत को संविधान की व्याख्या करते वक्त संविधान के सिद्धांतों पर फैसला देना होता है। ऐसा कोई संवैधानिक सिद्धांत नहीं है कि लोकतंत्र और उसके संस्थानों को चुने हुए जनप्रतिनिधियों से बचाया जाए। भारतीय लोकतंत्र गैर निर्वाचित लोगों का निरंकुश तंत्र नहीं बन सकता है और अगर चुने हुए लोगों को दरकिनार किया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। क्या चुनाव आयोग और कैग जैसी संस्थाएं योग्य विश्वसनीय नहीं हैं हालांकि वे निर्वाचित सरकारों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

ऐसे किसी व्यक्ति के रूप में जिसने संसद की तुलना में अदालत में अधिक साल बिताये हों, मैं भारतीय लोकतंत्र के बारे में बात करने को विवश हूँ। दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र में कोई सिद्धांत नहीं है कि लोकतंत्र की संस्थाओं को निर्वाचित संस्थाओं से बचाया जाये।

दिया गया स्पष्टीकरण एक मजबूत

एक संवैधानिक अदालत को संविधान की व्याख्या करते वक्त संविधान के सिद्धांतों पर फैसला देना होता है। ऐसा कोई संवैधानिक सिद्धांत नहीं है कि लोकतंत्र और उसके संस्थानों को चुने हुए जनप्रतिनिधियों से बचाया जाए। भारतीय लोकतंत्र गैर निर्वाचित लोगों का निरंकुश तंत्र नहीं बन सकता है और अगर चुने हुए लोगों को दरकिनार किया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। क्या चुनाव आयोग और कैग जैसी संस्थाएं योग्य विश्वसनीय नहीं हैं हालांकि वे निर्वाचित सरकारों द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

नींव पर दिया जाना चाहिए था। अगर एक नेता यह महसूस करता है कि आपातकालीन स्थिति का खतरा है, तो ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय ही इसे बचा सकता है। सत्तर के दशक के मध्य में जब आपातकाल घोषित किया गया था, वह मेरे जैसे लोग थे – राजनीतिज्ञ, जिन्होंने लड़ाई लड़ी और जेल गये। यह सर्वोच्च अदालत थी, जिसे झुकना पड़ा और इसलिए अदालत के लिए यह मान लेना कि वह अकेले राष्ट्र को आपातकाल से रक्षा कर सकती है, अतीत में झुठला दिया गया है। वैकल्पिक लैंगिकता का प्रतिनिधित्व करनेवाले लोगों के लिए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसे अपराधमुक्त कर दिया था। मैं वर्तमान सरकार का एक हिस्सा हूँ, लेकिन मैंने सार्वजनिक रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय की राय का समर्थन किया था। यह सर्वोच्च न्यायालय ही थी, जिसने इसे फिर से अपराध घोषित किया था। वैकल्पिक लैंगिकता के अनुयायी वर्ग को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने की धारणा को केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा संरक्षित किया जा सकता है, फिर से इतिहास द्वारा गलत साबित हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय की राय अंतिम है। यह अमोघ नहीं है।

यह फैसला संविधान के अनुच्छेद 124 और 217 के प्रावधान की व्याख्या करती है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से सम्बंधित है और अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से सम्बंधित है। दोनों अनुच्छेद भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किए जाने के अधिकार प्रदान करते हैं। संविधान का अधिदेश था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश मात्र एक परामर्शदाता हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति प्राधिकारी हैं। व्याख्या का बुनियादी सिद्धांत यह है कि एक कानून की एक विस्तारित अर्थ देने के लिए व्याख्या की जा सकती है, लेकिन प्रत्येक विपरीत मतलब के लिए उन्हें फिर से नहीं लिखा जा सकता है। दूसरे न्यायाधीश के मामले में, न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति प्राधिकारी और राष्ट्रपति को एक 'परामर्शदाता' घोषित कर दिया है। तीसरे न्यायाधीश के मामले में, न्यायालय ने न्यायाधीशों के कालेजियम के रूप में मुख्य न्यायाधीश की व्याख्या की है। राष्ट्रपति की प्रधानता को मुख्य न्यायाधीश या कालेजियम की प्रधानता के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। चौथे न्यायाधीश के मामले में (वर्तमान में) अनुच्छेद 124 और 217 की व्याख्या में

शेष पृष्ठ 26 पर

भाजपायुक्त भारत की ओर बढ़ती भाजपा

– प्रभात झा

आज से कुछ वर्ष पहले जब लोग कहा करते थे कि एक समय आएगा जब भारत कांग्रेसमुक्त हो जाएगा, लोग जवाब देते थे, कैसी बात करते हो? गंगा-यमुना सूख सकती है पर कांग्रेसमुक्त भारत नहीं हो सकता। दिल्ली में आयोजित भाजपा की राष्ट्रीय परिषद् बैठक में जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि हमें कांग्रेसमुक्त भारत करना है, तो उस समय भी बहुत लोगों के मन में यह बात नहीं उतरी थी। आज जब देश की राजनैतिक परिस्थिति को अखिल भारतीय स्तर पर देखते हैं तो लगता है, सच में नरेन्द्र मोदीजी ने आने वाले कल को पहचान लिया था। उनकी वाणी फलती जा रही है।

राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते जब हम कांग्रेस के इतिहास पर नजर डालते हैं तो लगता है कि सच में एक समय पूरे देश में कांग्रेस का बोलबाला था। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार में उनका गढ़ था, लेकिन आज जब नजर दौड़ाते हैं तो इन दोनों राज्यों में कांग्रेस सिमट ही नहीं गई, उखड़ सी गई।

उत्तर प्रदेश में 2014 की लोकसभा में 80 में से सिर्फ 2 सीटें, अमेठी और रायबरेली की जीत यह जाहिर करती है कि कांग्रेस कितनी कमजोर हो गई है। जब श्री नरेन्द्र मोदी अपने भाषणों में कहा करते थे कि यह मां-बेटे की पार्टी है तो कांग्रेस के लोग बुरा मानते थे। लेकिन सिर्फ मां-बेटे की जीत ने स्वत: यह सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस अब मां-बेटे की पार्टी ही रह गई है। कांग्रेस में पड़ रही इस अकाल का उनके किसी नेता को अंदाज नहीं आ रहा। किसी भी दल के अस्तित्व पर संकट नेतृत्व का संकट माना जाता है पर हाय री कांग्रेस! वह इस बात को आज भी समझने को तैयार नहीं है। राजनीति की बदलती संस्कृति, जिसमें चाटुकारिता और अपने से बौने लोगों की तलाश, यह दोनों बातें कांग्रेस ने पकड़ ली और यही कारण है कि वह कांग्रेसमुक्त भारत की ओर बढ़ रही है।

उत्तर प्रदेश में 2014 की लोकसभा में 80 में से सिर्फ 2 सीटें, अमेठी और रायबरेली की जीत यह जाहिर करती है कि कांग्रेस कितनी कमजोर हो गई है। जब श्री नरेन्द्र मोदी अपने भाषणों में कहा करते थे कि यह मां-बेटे की पार्टी है तो कांग्रेस के लोग बुरा मानते थे। लेकिन सिर्फ मां-बेटे की जीत ने स्वत: यह सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस अब मां-बेटे की पार्टी ही रह गई है। कांग्रेस में पड़ रही इस अकाल का उनके किसी नेता को अंदाज नहीं आ रहा। किसी भी दल के अस्तित्व पर संकट नेतृत्व का संकट माना जाता है पर हाय री कांग्रेस! वह इस बात को आज भी समझने को तैयार नहीं है।

मैं यह सब नहीं लिखता पर जब जम्मू-कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नजर दौड़ाता हूं तो देखने में आता है कि इतने बड़े भारत में कांग्रेस सात छोटे-मझौले राज्यों में और 2 बड़े राज्यों में सिमट कर रह गई है।

कहां एक समय देश में कांग्रेस का बोलबाला और जलजला था! वहीं कांग्रेस अब मात्र पूर्वोत्तर में- पांच राज्यों में सिसकियां ले रही है। कर्नाटक जाने के मुहाने पर खड़ा है और उत्तराखंड और हिमाचल में तो भाजपा पूर्व में शासन कर चुकी है। बात रही केरल की तो वहां उसकी वामपंथियों से सीधी लड़ाई है। नजर दौड़ाते हैं तो जम्मू-कश्मीर में, पंजाब में, दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, उड़ीसा में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आंध्रा में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, गोवा में कांग्रेस गायब है। ये भारत के वे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पूर्व में बहुत मजबूत थी। वैसे तो वामपंथियों की ताकत देखें तो वो भी देश में जिसे अपना गढ़ कहते थे पं. बंगाल वहां के स्थानीय निकाय तक से गायब हो गयी। केरल में वामपंथियों की धमनियों में रक्त समाप्त हो रहे हैं। मात्र त्रिपुरा में वामपंथी कहने को मौजूद है। जहां तक नजर दौड़ाएं तो बिहार में समाजवाद अंतिम सांस ले रहा है और उसके बाद उत्तर प्रदेश से भी समाजवाद उखड़ने की स्थिति में आ रहा है।

भारतीय राजनीति ने ऐसा दौर कभी नहीं देखा। स्थितियां इतनी बदल गई हैं कि पिछले दो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। आज भारतीय जनता पार्टी जनता के समर्थन के दम पर संसद में बहुमत है। कांग्रेस 543 में से लगभग 500 सीटों से गायब है। आज जब राजनैतिक गलियारों में चर्चा होती है तो यह बात लोग साफ तौर

पर कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम के कारण कांग्रेस का विस्तार हुआ था और यह भी कहने से नहीं चूकते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने परिवारवाद के चलते कांग्रेस को समाप्त कर दिया है। समझ में नहीं आता, जो बात जनता समझती है वह बात सोनियाजी और राहुल जी समझते हैं कि नहीं?

आजादी के बाद अब तक कांग्रेस कभी भी ऐसे नाजुक दौड़ से नहीं गुजरी। साथ ही भाजपा को जनता ने ऐसा सुनहरा अवसर पूर्व में कभी नहीं दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और भाजपा की पूरी टीम इसलिए नहीं मेहनत कर रही कि कांग्रेसमुक्त भारत करना है बल्कि उन्हें भाजपायुक्त भारत बनाना है। भाजपा ने इस दिशा में अपने कदम भी बढ़ाए हैं। और उसके एक नहीं अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं- मसला महाराष्ट्र का हो, हरियाणा का हो, झारखंड का हो, जम्मू-कश्मीर का हो या अब बिहार का हो, भाजपा उन सभी राज्यों में कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के समर्थन से अपना विस्तार कर रही है।

आजादी के बाद अब तक कांग्रेस कभी भी ऐसे नाजुक दौड़ से नहीं गुजरी। साथ ही भाजपा को जनता ने ऐसा सुनहरा अवसर पूर्व में कभी नहीं दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह और भाजपा की पूरी टीम इसलिए नहीं मेहनत कर रही कि कांग्रेसमुक्त भारत करना है बल्कि उन्हें भाजपायुक्त भारत बनाना है।

बिहार के चुनाव में यह आम चर्चा का विषय है कि बिहार की सभी सीटों पर लड़नेवाली कांग्रेस की यह दयनीय स्थिति क्यों बनी कि वह मात्र 41 सीटों पर लड़ रही है। बिहार के चुनाव में यह भी चर्चा का विषय है कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाली राजद-जदयू डूबती कांग्रेस का समर्थन क्यों ले रहे हैं? चर्चा यह भी है कि जिस जदयू ने पानी पी-पीकर राजद को कोसा था वह अब सिर्फ कुर्सी के लिए एक हो गये। लोग यह भी कह रहे हैं कि भाजपा ने अपने कंधे पर बिठाकर नीतीश कुमार को बिहार का नेता बना दिया था क्योंकि आज भी गांव-गांव में किसी एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में पराजित होने के बाद जीतनराम माझी को क्यों मुख्यमंत्री बनाया और कुछ ही माह बाद क्यों हटा दिया?

जदयू-राजद और कांग्रेस भले ही इन चर्चाओं को न सुन रही हो पर सच्चाई यही है कि ये सभी चर्चाएं जन-जन के बीच चल रही हैं। बिहार देश में बौद्धिक स्तर पर अग्रणी राज्य की पंक्ति में है लेकिन ऐसे बौद्धिक संपदा वाले बिहार की जो दुर्दशा इन तीनों दलों ने की उसे बिहार की जनता भूल नहीं सकती। भाजपा-जदयू की सरकार जब बनी तो लोग बिहार से पलायन करना बंद कर चुके थे।

यहां तक कि पलायन कर चुके बिहारी बिहार की ओर लौटने लगे थे। लेकिन आज उन सभी बिहारियों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। बिहार देश के अन्य राज्यों से बहुत पिछड़ गया है। आज भी अगर यूपीएससी की परीक्षा परिणाम देखें तो उनमें सर्वाधिक लोग बिहार से चयनित होते हैं। मीडिया पर नजर डालें तो बिहारियों का ही बोलबाला है। जाति के आधार पर राजनीति करने वाले कुछ नेताओं ने बिहार को जाति की आग में झोंक दिया।

देश प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर देख रहा है। खासकर आने वाली पीढ़ी उन्हें अपना प्रेरणा मानती है। आज विश्व में जो भारतीय हैं वे भी आज गौरव महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चीन और अमेरिका के राष्ट्र प्रमुखों को महात्मा गांधी द्वारा भाषित गीता भेंट की। गीता विश्व बंधुत्व का ज्ञान देता है। कांग्रेस के जमाने में रहे किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसे विचार क्यों नहीं प्रस्तुत किए? 'योग' हमारी मिट्टी का सुगंध है, इसे विश्व स्तर पर फैलाने का काम यूएन में जाकर जिसने किया उसका नाम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी है। गांव के गरीब की और शहर के नौजवानों की सबसे पहले चिंता आज एनडीए सरकार ने की है। केन्द्र सरकार की आधारहीन आलोचना से कांग्रेस का भला नहीं होगा। कांग्रेस का भला तो नेतृत्व बदलने से होगा, जो कांग्रेस में संभव नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी गिर रही कांग्रेस की चर्चा कम करे और बढ़ती भाजपा की चर्चा अधिक करे तो देश में भाजपा विचार की स्वीकार्यता बढ़ती जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह के टीम की मेहनत देखकर राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि आने वाले दिनों में वह दिन दूर नहीं जब देश भाजपायुक्त होगा और जब भाजपायुक्त होगा तो देश स्वत: कांग्रेस से मुक्त होगा। ■

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद हैं)

पुण्य स्मरण

ईमानदारी और प्रतिबद्धता का दूसरा नाम केदारनाथ

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा

आज जहां लोग काम करते कम और दिखावा ज्यादा करते हैं, वहीं हमारे समय में केदारनाथ साहनी जी के बारे में कहा जाता है कि जितना वे करते हैं उसका दसांश भी नहीं दिखाते थे। अगर ईमानदारी और प्रतिबद्धता की बात एक साथ की जाए तो फिर केदारनाथ साहनी जैसा कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। एक और बात कही जाती है कि ईमानदार व्यक्ति का हाथ हमेशा बंधा रहता है लेकिन इस मामले में वे बिल्कुल भिन्न थे। वे जितने ईमानदार थे उतने ही दयालु। वे लोगों की बहुत दूर तक जाकर मदद करने को तैयार रहते थे। मदद करने में उन्होंने कभी अपने और परायों में कोई भेद नहीं किया। तभी तो उनके जैसे शख्स की आज भी हर क्षेत्र में उतनी ही जरूरत है जितनी कल थी। काल ने किसी को नहीं छोड़ा है इसलिए उन्हें भी नहीं छोड़ा, लेकिन साहनी जी अपनी कीर्ति से कालातीत बन गए। उनका स्वर्गवास 3 अक्टूबर, 2012 को दिल्ली में हो गया।

केदारनाथ साहनी का जन्म अखंडित भारत के रावलपिंडी जिला में 24 अक्तूबर 1926 को हुआ था जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गृहनगर में ही हुई थी। जम्मू के प्रिंस ऑफ वेल्स कालेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। वहीं वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गए। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनकी सेना में अच्छे पद पर नौकरी लगी थी लेकिन उन्होंने नौकरी का नहीं सेवा का रास्ता चुना।

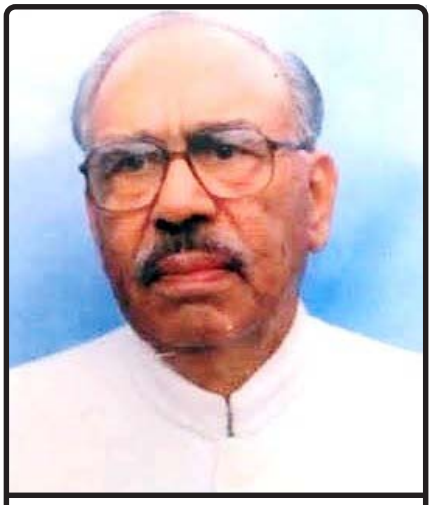

अगर ईमानदारी और प्रतिबद्धता की बात एक साथ की जाए तो फिर केदारनाथ साहनी जैसा कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता।

वे संघ के प्रचारक हो गए। उन्हें जम्मू-कश्मीर के मीरपुर में भेजा गया। 1947 में कबायली हमले के नाम पर पाकिस्तान ने जब जम्मू-कश्मीर पर आक्रमण किया तो मीरपुर में अपने प्राणों पर खेल कर उन्होंने हिन्दू-सिखों की सुरक्षा का प्रबंध किया और उन्हें वहां से निकालने में अत्यन्त वीरतापूर्वक काम किया। बाद में वह पंजाब के प्रचारक के रूप में कार्य करते रहे। पाकिस्तानी हमले का पुरजोर जवाब देने वाले लोगों में शामिल अधिकांश केदारनाथ साहनी के तैयार किए गए संघ के कार्यकर्ता थे। 1954 में साहनी जी को जनसंघ का भार संभालने के लिए दिल्ली भेजा गया। उस समय अनुशासनहीनता के कारण दिल्ली जनसंघ के कई पदाधिकारियों को पार्टी से निकाल दिया गया था। उस कठिन दौर में साहनी जी ने अथक परिश्रम कर पार्टी के पैर जमाने में अहम किरदार निभाया। पहले साइकिल पर, फिर स्कूटी पर, फिर बुलेट मोटरसाइकिल पर उन्होंने घोर परिश्रम किया। वह साइकिल, मोटरसाइकिल चलाते थे और मैं उनके पीछे बैठकर दिल्ली के सभी देहातों, बस्तियों और शहरी इलाकों में दिन-रात घूमता रहता था। इतने कठिन परिश्रम का परिणाम यह हुआ कि वह साल 1956 में काफी बीमार हो गए। इतने बीमार कि वे बिस्तर से उठ नहीं पाते थे, बिस्तर पर ही उनका इलाज किया गया लेकिन इस दौरान मैंने उनमें जो खास बात देखी वह यह कि बीमारी के बावजूद बिस्तर से ही पार्टी का काम लगन के साथ करते रहे।

1958 में दिल्ली में जब कार्पोरेशन बना तो जनसंघ की ओर से वह एल्डरमैन चुने गए और जनसंघ निगम दल के नेता बने और मैं उनके साथ मुख्य सचेतक का काम करता रहा। इसी दौरान साल 1959 में स्वतंत्र 'निर्दलीय' सदस्यों और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत अरुणा आसफ अली महापौर चुनी गई और केदारनाथ साहनी उपमहापौर चुन लिए गए। उपमहापौर के रूप में उनका कार्यकाल महज एक साल का रहा। 1967 में जब दिल्ली नगर निगम और महानगर परिषद में जनसंघ को बहुमत मिला तो वे फिर से दल के नेता चुने

गए और स्थाई समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। फिर आगे चलकर साहनी जी दिल्ली नगर निगम के महापौर बन गए। इसके बाद साहनी जी दिल्ली महानगर परिषद के मुख्य कार्यकारी पार्षद, जो कि आज के मुख्यमंत्री के बराबर का पद हुआ करता था, बने। भारतीय जनसंघ के रूप में जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जनता पार्टी के टूटने पर 1984 में भारतीय जनता पार्टी सामने आई। भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद वे दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। इसके बाद उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदि पदों पर रहते हुए अत्यन्त कुशलतापूर्वक कार्य किया इन सब महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए उन्होंने ईमानदारी के उच्चतम आदर्श कायम किए। साहनी जी ने कई मौकों पर अपनी ईमानदारी को तरजीह दी है चाहे नतीजा जो भी निकला हो।

मैं मुख्य कार्यकारी पार्षद था और साहनी जी नगर निगम में दल के नेता होने के साथ ही स्थायी समिति के अध्यक्ष भी थे। उस दौरान हम लोगों ने यह तय किया कि नौकरियों, ठेकों, अलाटमैंट और नियुक्तियों को पूर्ण रूप से पारदर्शी बनाने के लिए या तो खुले में टैंडर निकालने की व्यवस्था की जाए या फिर शैक्षणिक योग्यता अथवा लाटरी द्वारा दिया जाए। साहनी जी भी जानते थे और हम भी जानते थे कि इससे नाराजगी बढ़ेगी। वह स्वाभाविक भी थी, क्योंकि नई व्यवस्था लागू हो जाने से स्वेच्छा से लाभान्वित नहीं किया जा सकता था लेकिन साहनी जी ने नई व्यवस्था का समर्थन किया।

साहनी जी जब भी किसी की संस्तुति करते हुए पत्र लिखते तो यह जरूर लिखते थे कि इसे नियमपूर्वक देखा जाए। बाद में उनकी इस आदत से रोष में आए कार्यकर्ताओं ने उनका नाम ही नियमानुसार रख दिया। साहनी जी इसकी भी परवाह नहीं करते थे कि लोग उन्हें क्या कहते हैं या फिर कैसे लेते हैं।

इसीलिए महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए व अधिकार सम्पन्न होते हुए भी विरोधी पार्टियों ने भी कभी उन पर कोई दोषारोपण नहीं किया। बेसहारा और अभावग्रस्त महिलाओं को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से एक संस्था बनाने का दायित्व आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी मदनदास देवी ने केदारनाथ साहनी को सौंपा। साहनी जी ने यह भूमिका भी बखूबी निभाई।

(साभार- पंजाब केसरी)

पृष्ठ 22 का शेष...

नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश की 'विशिष्टता' को अंतर्निहित कर दिया गया है और राष्ट्रपति की भूमिका को लगभग पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। कानून की व्याख्या का कोई सिद्धांत दुनिया में न्यायिक संस्थाओं को संविधान सभा के उलट संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार क्षेत्र नहीं देता है। इस फैसले में यह दूसरी बुनियादी गलती है। न्यायालय केवल व्याख्या कर सकती है – यह एक कानून को दुबारा लिखने का तीसरा प्रकोष्ठ नहीं हो सकता।

99 वें संविधान संशोधन को खारिज कर के न्यायालय ने फिर से कानून बनाने का फैसला किया। अदालत ने 99 वें संविधान संशोधन को खारिज कर दिया। अदालत को ऐसा करने का अधिकार है। इस संशोधन को खारिज करते हुए, निरस्त अनुच्छेद 124 और 217 के प्रावधानों को फिर से कानून बना दिया गया जो केवल विधायिका कर सकती है। इस फैसले में यह तीसरी बुनियादी गलती है।

चौथा सिद्धांत जिस आधार पर यह फैसला गलत साबित होता है, कॉलेजियम प्रणाली, जोकि न्यायिक कानून का एक उत्पाद है, की चर्चा करते हुए कहा गया कि यह दोषपूर्ण है। इसके सुधार के लिए एक सुनवाई तय की गई। न्यायालय ने फिर तीसरे प्रकोष्ठ होने के भूमिका की धारणा बना ली। यदि न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया के साथ कोई समस्या है, तो क्या उन विधायी परिवर्तनों को विधायिका के बाहर विकसित किया जाना है?

ऐसे व्यक्ति के रूप में, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भारतीय संसद की संप्रभुता के बारे में समान रूप से चिंतित है, मेरा मानना है कि दोनों जरूरी है और दोनों का सह-अस्तित्व होना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना है। इसे मजबूत बनाने के लिए, किसी को संसदीय संप्रभुता को कमजोर करने की जरूरत नहीं है जो न केवल एक आवश्यक बुनियादी संरचना है, वरन हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। ■

(लेखक-केन्द्रीय वित्त व सूचना प्रसारण मंत्री हैं)

'एक गढ़ी हुई बगावत – अन्य साधनों द्वारा राजनीति'

केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री अरुण जेटली ने दादरी में अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति की हत्या को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को सही सोच वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी इसे न तो तर्कसंगत ठहरा सकता है और न ही नजरअंदाज कर सकता है। इस तरह की घटनाओं से देश का नाम खराब होता है।

इस घटना के बाद, बहुत सारे लेखकों ने साहित्य अकादमी द्वारा उन्हें प्रदत्त पुरस्कार लौटा दिया है। लेखकों के विरोध के रुझान से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान केंद्र सरकार के अधीन देश में असहिष्णुता का माहौल बन गया है।

क्या यह विरोध सचमुच का है या फिर गढ़ा हुआ? क्या यह वैचारिक असहिष्णुता का मामला नहीं है? बड़े पैमाने पर वाम विचारधारा या नेहरूवादी विचारधारा की ओर झुकाव रखने वाले लेखकों को पिछली सरकारों द्वारा मान्यता दी गई थी। उनमें से कुछ इस मान्यता के हकदार रहे होंगे। मैं न तो उनकी शैक्षणिक योग्यता और न ही उनके राजनीतिक पूर्वाग्रह रखने के अधिकार पर सवाल उठा रहा हूँ। उनमें से कई लेखकों ने वर्तमान प्रधानमंत्री के खिलाफ उस वक्त भी आवाज बुलंद की थी जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। जिन लोगों ने इससे पूर्व की सरकार के समय सरपरस्ती का आनंद लिया था, नई सरकार के मई, 2014 में शपथ लेने के बाद, जाहिर तौर पर वे लोग वर्तमान सरकार के साथ असहज हो गए हैं। यह बेचैनी भारत में एक अन्य राजनीतिक वास्तविकता के कारण और आगे बढ़ चुकी है। सिकुड़ते जनाधार के साथ, कांग्रेस पुनरुद्धार के कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। वामपंथी पार्टियाँ बड़ी तेजी से हाशिये पर धकेल दी गई है। मोदी-विरोधी और भाजपा-विरोधी वर्गों की नई रणनीति 'अन्य साधनों द्वारा राजनीति' करने के उपाय करने के लिए प्रतीत होता है। सबसे आसान तरीका एक संकट का निर्माण और बाद में एक फर्जी संकट के मद्देनजर सरकार के खिलाफ एक कागजी बगावत का निर्माण करना है।

वर्तमान सरकार के शपथ के कुछ महीनों बाद, चर्चों सहित ईसाई समुदाय के खिलाफ एक के बाद एक कई हमलों की खबरें मीडिया में छाई रही। विरोध मार्च का आयोजन किया गया। यह आरोप लगाया गया कि देश में अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहा है। उनमें से प्रत्येक 'हमलों' की जांच की गई और उनमें से ज्यादातर मामलों में चोरी या एक खिड़की तोड़ने के लिए बोतलें फेंकने के रूप में छोटे-मोटे अपराधों की घटनाएं पाई गई। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के हमलों में से किसी के लिए भी धर्म या राजनीति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सका। पश्चिम बंगाल में एक नन के साथ बलात्कार करने के मामले का मुख्य आरोपी बांग्लादेशी मूल के एक व्यक्ति को पाया गया। उस समय के विरोध ने दो कारकों पर प्रकाश डाला था। पहली बात यह कि यह अल्पसंख्यक समुदाय के संस्थानों के ऊपर हमला था और दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री इन हमलों के बारे में चुप थे। जब यह बात साबित हो गई कि 'हमलों' के ये मामले आपराधिक घटनाएं थीं, तो प्रचार और प्रचारक दोनों परिदृश्य से गायब हो गए।

मोदी सरकार के खिलाफत के लिए, विरोध कर रहे लेखकों ने कोई मुद्दा तलाशने के लिए कड़ा संघर्ष किया है। तर्कवादी श्री एम.एम. कलबुर्गी की कर्नाटक में गोली मारकर हत्या कर दी गई जो एक कांग्रेस शासित राज्य है। महाराष्ट्र में 20 अगस्त 2013 को एक और तर्कवादी, श्री एन दाभोलकर की हत्या कर दी गई, उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार थी। दोनों घटनाओं की साफ शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। राज्य में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और हमले के आसान निशाने को सुरक्षा देना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इसी तरह, दादरी घटना उत्तर प्रदेश में घटित हुई, जहाँ समाजवादी पार्टी का शासन है। 'अन्य साधनों द्वारा राजनीति' ने अब एक वैकल्पिक रणनीति तय कर लिया है। तीनों अपराधों को जोड़ो, सच पर झूठ का आवरण चढ़ाओ और उन सबको वर्तमान केंद्र सरकार के ऊपर डाल दो। किसी ने भी इन अपराधों में किसी भी तरह की सरकारी ढिलाई बरतने का आरोप नहीं लगाया है।

लेकिन किसी बगावत को गढ़ने के लिए, यह जरूरी है कि सच्चाई को अँधेरे में रखा जाए और यह धारणा बनाई जाय कि मोदी सरकार इन अपराधों के लिए जिम्मेदार है, भले ही ये घटनाएं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शासित राज्यों में में ही क्यों न घटित हुई हो। वास्तव में, 2015 में विरोध कर रहे लेखकों में से एक ने अपने पद्मश्री पुरस्कार को लौटाते समय दिए गए कारणों में से एक के रूप में 1984 के सिख हत्याओं का हवाला दिया। 1984 के नरसंहार के लिए इस लेखिका के विवेक के जाग्रत होने में इकत्तीस साल लग गये। देश में असहिष्णुता का कोई माहौल नहीं है। गढ़ा हुआ विरोध भाजपा के प्रति एक वैचारिक असहिष्णुता का मामला है।

विरोध प्रदर्शन करने वालों के लिए कुछ सवाल: उनमें से कितनों ने आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी या अपनी गिरफ्तारी दी थी अथवा विरोध प्रदर्शन किया था। क्या इन लेखकों ने 1984 के सिख हत्याओं या 1989 के भागलपुर दंगों के खिलाफ बोला? क्या उनकी अपनी अंतरात्मा की आवाज 2004 और 2014 के बीच करोड़ों लाखों के भ्रष्टाचार से हिली नहीं थी?

कांग्रेस अपने पुनरुद्धार के कोई संकेत नहीं दिखा रही है और महत्त्वहीन वामपंथ अपनी विधायी प्रासंगिकता खो रही है, तो अतीत के संरक्षण में फले-फूले अब 'अन्य साधनों द्वारा राजनीति' का अब सहारा ले रहे हैं। लेखकों का गढ़ा हुआ विरोध ऐसा ही एक मामला है।■

(लेखक- केन्द्रीय वित्त एवं सूचना प्रसारण मंत्री हैं।)

स्वच्छ भारत, स्वच्छ हिमालय अभियान का शुभारंभ

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजु ने 12 अक्टूबर को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के स्वच्छ भारत, स्वच्छ हिमालय अभियान को हरी झंडी दिखाई। श्री रिजिजु ने अपने स्वर्ण जयंती आरोहण के एक हिस्से के रूप में इस महान कार्य को शुरू करने पर बीएसएफ की सराहना की और कहा कि स्वच्छता हम सबों के लिए जीवन का एक रास्ता बन जाए, इसके पहले बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाए जाने की जरूरत है।

श्री रिजिजु ने कहा कि उन्होंने जिन देशों की यात्राएं की हैं, उनमें से ज्यादातर देशों की समाजों और वहां के लोगों के लिए स्वच्छता एक अंदरूनी हिस्सा है। लेकिन अपने देश में स्वच्छता, अनुशासन और व्यवस्था के मोर्चे पर अभी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तक को लाल किले के प्राचीर से इसे एक आम अभियान के रूप में शुरू करने की आवश्यकता को रेखांकित करने को मजबूर होना पड़ा। यह जानकारी देते हुए कि ठसाठस भरे होने के बावजूद जापान के मेट्रो पूरी तरह साफ होते हैं, उन्होंने बताया कि जरूरत से अधिक भीड़ और घनी आबादी गंदे जीवन के बहाने नहीं हो सकते।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बर्ताव में बदलाव लाने की जरूरत है

यह गौर करते हुए कि कैंटीन समेत सुरक्षा बलों के परिसर अपने स्वच्छ वातावरण के लिए जाने जाते हैं, श्री रिजिजु ने उम्मीद जताई कि बीएसएफ स्वच्छ हिमालय जागरूकता अभियान देश के कोने-कोने में स्वच्छता के महान संदेश को भेजने में समर्थ होगा।

इस अवसर पर बीएसएफ के महानिदेशक श्री बी.के. पाठक ने कहा कि बीएसएफ के 'स्वच्छ भारत, स्वच्छ हिमालय' अभियान का संचालन 12 अक्टूबर, 2015 से 23 नवंबर, 2015 तक किया जाएगा और इसमें साइकिल चलाने, व्हाईट वाटर राफ्टिंग और गढ़वाल के हिमालय में ट्रैकिंग अभियान शामिल है।

इस दौरान टीम के सदस्य उस पूरे और अपशिष्ट सामग्रियों को वापस ले आएंगे जिन्हें हिम नदियों पर छोड़ दिया गया है। ■

रिपोर्ट

महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण

राम नयन सिंह

भाजपानीत राजग सरकार की बेहतर नीतियों व सुप्रबंधन के चलते महंगाई पर प्रभावी नियंत्रण लगा है। थोक मुद्रास्फीति लगातार 11वें महीने शून्य के नीचे बनी हुई है। खुदरा मुद्रास्फीति भी कांग्रेसनीत संप्रग सरकार के लगातार दहाई अंकों से घटकर साढ़े पांच प्रतिशत के आसपास बनी हुई है। देश में महंगाई की मार कम हुई है, इस बात का अंदाजा रिजर्व बैंक के हालिया रेपो रेट में 0.50 प्रतिशत की कटौती से भी लगाया जा सकता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से प्याज और दाल की कीमतें नियंत्रित नहीं रही, लेकिन इसकी वजह केंद्र सरकार की नीतियां नहीं, बल्कि मौसम की मार, आवक की कमी और अन्य वजहें हैं।

कुछेक वर्ष पहले एक समय था जब एक-दो नहीं, बल्कि सालों-साल महंगाई की दर दहाई अंकों के आसपास बनी रही। यह कांग्रेसनीत संप्रग सरकार की कुनीतियों का खामियाजा था, जो देश की गरीब व मध्यम वर्गीय जनता ने सालोंसाल झेला। पिछले साल मई में मोदी सरकार ने देश का नेतृत्व संभाला। भाजपानीत राजग सरकार ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कई प्रभावकारी कदम उठाए, जिसका असर कुछ ही महीनों में दिखाई पड़ने लगा। साथ ही, पेट्रोलियम पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में आई कमी के कारण भी महंगाई पर असर पड़ा।

प्याज और दालों को छोड़कर लगभग सभी वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में है। थोक मुद्रास्फीति लगातार 11वें महीने शून्य से नीचे बनी हुई है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में शून्य से 4.54 प्रतिशत नीचे रही। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति एक महीने पहले अगस्त में शून्य से 4.95 प्रतिशत नीचे थी। थोक मुद्रास्फीति पिछले साल नवंबर से लगातार शून्य से नीचे बनी हुई है। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में थोक मुद्रास्फीति 2.38 प्रतिशत पर थी।

दालों की कीमतों पर काबू के लिए सरकार की कोशिशें लगातार जारी है। पिछले जून में दालों की कीमतों पर प्रभावी व स्थायी नियंत्रण हेतु केंद्र सरकार ने दालों के समर्थन मूल्य में भारी इजाफा किया। इस इजाफे का असर दालों की बुआई पर पड़ा। मौसम विभाग द्वारा मानसून की लगातार दूसरे साल कमी की भविष्यवाणी होने के बावजूद भी दालों की बुलाई का क्षेत्र 12 प्रतिशत बढ़ा, वहीं मानसून की भारी कमी के कारण धान की रोपाई-बुवाई का क्षेत्र घट गया। यह इस बात का प्रमाण है कि भाजपानीत केंद्र सरकार के प्रयासों का असर दालों की बुवाई पर पड़ा।

खाद्य उत्पादों में मुद्रास्फीति, सितंबर में 0.69 प्रतिशत हो गई जबकि अगस्त में यह शून्य से 1.13 प्रतिशत नीचे थी। सब्जियों की मुद्रास्फीति शून्य से 9.45 प्रतिशत नीचे रही जो कि अगस्त में शून्य से 21.21 प्रतिशत नीचे थी। सब्जियों का भाव सालाना आधार पर 9.45 प्रतिशत और आलू 57.34 प्रतिशत घटा है। वहीं दूध व गेहूं की कीमतें बहुत ही मामूली रूप से बढ़ी है। दूध 2.16 प्रतिशत, गेहूँ 3.34 प्रतिशत बढ़ा है। ईंधन और बिजली वर्ग में मुद्रास्फीति की दर सितंबर में शून्य से 17.71 प्रतिशत नीचे रही, जबकि विनिर्मित उत्पादों की महंगाई दर शून्य से 1.73 प्रतिशत रही। सिर्फ प्याज और दलहन में मूल्य वृद्धि जारी रही। सितंबर माह में प्याज का दाम 113.70 प्रतिशत बढ़ गया जबकि दालों के दाम 38.56 प्रतिशत बढ़ गये। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में प्याज की कीमतें कम हुई हैं। प्याज की कीमतें मौसमी कारणों से घटती-बढ़ती हैं। इस साल दलहन की कीमतों में उछाल का प्रमुख कारण मौसम की मार है। फसल खराब होने के चलते आवक में कमी आई है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दालों की कमी है, इससे भी दालों की कीमतों पर असर पड़ रहा है। साथ ही दालों की महंगाई के लिए राज्य सरकारें भी जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार के सामने यह चुनौती इसलिए भी बड़ी है, क्योंकि राज्य सरकारें केंद्र से दाल लेने को तैयार नहीं हैं। अभी तक सिर्फ दो राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने केंद्र से दाल की मांग की है।

दालों की कीमतों पर काबू के लिए सरकार की कोशिशें लगातार जारी है। पिछले जून में दालों की कीमतों पर प्रभावी व स्थायी नियंत्रण हेतु केंद्र सरकार ने दालों के समर्थन मूल्य में भारी इजाफा किया। इस इज़ाफे का असर दालों की बुआई पर पड़ा। मौसम विभाग द्वारा मानसून की लगातार दूसरे साल कमी की भविष्यवाणी होने के बावजूद भी दालों की बुलाई का क्षेत्र 12 प्रतिशत बढ़ा, वहीं मानसून की भारी कमी के कारण धान की रोपाई-बुवाई का क्षेत्र घट गया। यह इस बात का प्रमाण है कि भाजपानीत केंद्र सरकार के प्रयासों का असर दालों की बुवाई पर पड़ा। तात्कालिक रूप से दालों की कीमतों पर नियंत्रण हेतु केंद्र सरकार ने बड़ी मात्रा में दालें आयात की है।

खुशी की बात यह है कि पहली खेप में 3250 टन अरहर दाल देश पहुँच गई है। इतना ही नहीं, नई फसल आने के बाद भी दाल का आयात होगा ताकि दालों की कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके। साथ ही सरकार दालों का बफर स्टॉक बनाएगी। ■

पृष्ठ 17 का शेष...

कि श्री नीतीश कुमार हमेशा से विश्वासघात करने की राजनीति करते आये हैं, पहले उन्होंने कांग्रेस से समझौता कर लोकनायक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और जननायक कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों के साथ विश्वासघात किया, लालू जी से हाथ मिलकर राज्य की जनता के जनादेश के साथ विश्वासघात किया और फिर एक दलित के बेटे को राज्य के मुख्यमंत्री पद से हटाकर, राज्य की सत्ता पर काबिज होकर बिहार के दलित के साथ भी विश्वासघात करने का पाप किया है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि महास्वार्थबंधन के नेताओं का अहंकार बिहार के विकास में मुख्य बाधक है।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जनता के समेकित विकास और गरीबों एवं पिछड़ों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं चाहे वह प्रधानमंत्री जन-धन सुरक्षा योजना हो, या 12 रूपए और 330 रुपये सालाना के हिसाब से जीवन सुरक्षा बीमा या जीवन ज्योति बीमा योजना हो या फिर छोटे-मोटे रोजगार के लिए गरीबों को मुद्रा बैंक योजना के तहत आसान ऋण उपलब्ध कराने की बात हो। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा-नीत राजग की सरकार बनती है तो यहां के बेरोजगारों को मुम्बई और दिल्ली की ओर रुख नहीं करना पडेगा। उन्होंने कहा कि हमने अपने घोषणापत्र में समाज के पिछड़ों, अति-पिछड़ों, दलितों, महादलितों, शोषितों और वंचितों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं का प्रावधान किया है और यदि बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हम अनवरत रूप से राज्य के जनता की भलाई की दिशा में काम करेंगे। श्री शाह ने कहा कि अगर बिहार में अपराध, भ्रष्टाचार और जंगलराज से मुक्ति चाहिए, रोजगार एवं निवेश चाहिए, तकनीकी शिक्षा चाहिए, गरीबों और पिछड़ों की स्थिति में सुधार चाहिए तो बिहार की जनता को एकमत से फैसला करके राज्य में दो-तिहाई की पूर्ण बहुमत से भाजपा-नीत सरकार बनानी होगी। ■

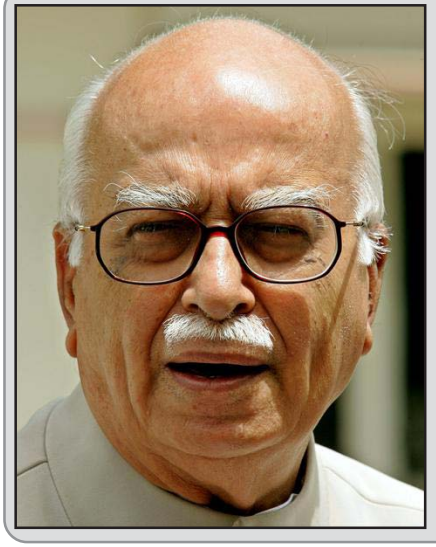

जीवेम शरदः शतम्!

जन्मदिवस : 8 नवंबर

कमल संदेश परिवार भारत के पूर्व उपप्रधानमंत्री एवं भाजपा के मार्गदर्शक श्री लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन पर उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता है।